▪ RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 196 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » बुधवार » 11-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 नरवणे ने अपनी किताब का लिंक 2023 में साझा किया था, वह झूठ नहीं बोलेंगे : राहुल

6 मानसिक तनाव से जूझते समाज की बिखरती संवेदनाएं

7 राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

भारत सरकार

पशुधन विकास के कार्यों से मज़बूत होगी आजीविका, समृद्ध होंगे परिवार

अब बनेंगे पशु, मत्स्य और पोल्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G

(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025

125 दिन की रोज़गार गारंटी

CBC 35101/13/0113/2526

फर्स्ट टेक

नोटिस मामले के निपटारे तक आसन पर नहीं बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस दिए जाने के बाद मंगलवार को फैसला किया कि वह इस मामले का निपटारा होने तक आसन पर नहीं बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों ने बताया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत यह फैसला किया है कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वह अध्यक्षीय आसन पर नहीं बैठेंगे। बिरला ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि वह विपक्ष के नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई करें। विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

बिरला ने विपक्ष के नोटिस की जांच का निर्देश दिया

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया कि उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के

नोटिस की जांच करें। सूत्रों के अनुसार, बिरला ने महासचिव को निर्देश दिया है कि वह इस नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई करें। विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

11-02-2026 सूर्यास्त 6:13 बजे | 12-02-2026 सूर्योदय 6:34 बजे

BSE	NSE
84,273.92 (+208.17)	25,935.15 (+67.86)

सोना	चांदी
16,260 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	279,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

कद की भद

है लोकतंत्र में नहीं खुदा,
कोई भी मंत्री या सांसद।
सब संविधान के हैं अधीन,
सबको है खबर सभी की हद।
करते विरोध जो जायज का,
कुछ वोटों का पा करके मद।
विस्मृत करके वे अपना कद,
उड़वाते हैं खुद की खुद भद।।

विपक्ष ने बिरला को हटाने के लिए नोटिस दिया

लोकसभा अध्यक्ष पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की ओर से नोटिस सौंपे जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने फैसला किया कि वह मामले का निपटारा होने तक आसन पर नहीं बैठेंगे और उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया कि नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली/भाषा। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की ओर से नोटिस सौंपे जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने फैसला किया कि वह मामले का निपटारा होने तक आसन पर नहीं बैठेंगे और उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया कि नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। सूत्रों ने यह भी कहा कि नोटिस पर विचार किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सचेतक मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह नोटिस सौंपा। उल्लेखनीय है कि विपक्ष को दो बार नोटिस सौंपना पड़ा क्योंकि पहली बार जो नोटिस सौंपा गया था कि उसमें सदन के भीतर कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते समय जिन तिथियों का हवाला दिया गया था उनमें त्रुटि थी।

नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के करीब 120 सांसदों से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस सौंपा गया है। नोटिस में कहा गया है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस देते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, वह खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण है। कई अवसरों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि यह संसद में उनका मूल लोकतांत्रिक अधिकार है।

विपक्ष ने नोटिस में कहा, ''बीते दो फरवरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। करीब-करीब हमेशा ही ऐसा होता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता।'' उन्होंने दावा किया कि गत 3 फ़रवरी को, विपक्ष के आठ सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए ''मनमाने ढंग से'' निलंबित कर दिया गया और उन्हें केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया जा रहा है।

नोटिस में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर कहा गया है, बीते चार फ़रवरी 2025 को, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर पूरी तरह आपत्तिजनक और व्यक्तिगत हमले करने की अनुमति दी गई और स्थापित परंपराओं व मर्यादा के मानदंडों की अवहेलना करने के बावजूद उन्हें एक बार भी नहीं टोका गया। हमारे अनुरोध के बावजूद इस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वह आदतन ऐसी गतिविधियां करते हैं।

विपक्ष ने ओम बिरला द्वारा सदन में पांच फरवरी को दिए गए उस वक्तव्य का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चार फरवरी को कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता (प्रधानमंत्री) की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए। नोटिस में आरोप लगाया गया है, ये टिप्पणियां कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ खुले तौर पर झूठे आरोप लगाने वाली और अपमानजनक प्रकृति की हैं। अध्यक्ष, जिन्हें कार्य-संचालन नियमों और संसदीय मर्यादा के मानकों का संरक्षक होना चाहिए, उन्होंने सदन के पटल से ऐसे बयान दिए, जो इस संवैधानिक पद के दुरुपयोग को दर्शाते हैं।

विपक्ष ने कहा, ''हम लोकसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सम्मान देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, उससे हम अत्यंत आहत और व्यथित हैं।'' संविधान के अनुच्छेद 94 (1) (ग) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले दो या इससे अधिक सदस्यों द्वारा नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। नोटिस स्वीकार होने के बाद सदन में प्रस्ताव लाया जाता है।

अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के समय अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इस दौरान उपाध्यक्ष या पीठासीन सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार करने के लिए जरूरी है कि इस पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर लोकसभा अध्यक्ष पद से हट जाता है।

'कयामत' का दिन कभी नहीं आने वाला, बाबरी ढांचा भी कभी दोबारा नहीं बनेगा : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बाराबंकी/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि 'कयामत' का दिन कभी नहीं आने वाला है और इसलिए बाबरी ढांचा भी कभी दोबारा नहीं बनेगा। आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक कार्यक्रम में कहा, ''हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे'। मंदिर बन गया है। क्या कोई शक है? उन्होंने कहा, 'कयामत' का दिन कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण भी कभी होना ही नहीं है। जो लोग कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। कभी वह वक्त नहीं आने वाला है। श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय ने नौ नवंबर 2019 को फैसला देते हुए अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में दी गई पांच एकड़ की जमीन पर अभी तक कोई भी निर्माण नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद वह गौरवशाली क्षण (राम मंदिर का निर्माण) हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा-महाराजा आये, अनेक सरकारें आयीं। वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ और 1952 में पहले चुनाव के बाद सरकारें बनती गईं मगर अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण कराने की बात आखिर उनके मन में क्यों नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं। जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी समय राम को भूल जाते हैं इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी, यानी रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, रामकाज में बाधक थे और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, उनको हम बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है।

नोटिस देने से पहले एक बार बिरला से बात करनी चाहिए थी : अभिषेक बनर्जी

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं है,

लेकिन यह कदम उठाने से पहले विपक्षी दलों को लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी शिकायतें रखनी चाहिए थी। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य बनर्जी ने कहा कि विपक्ष द्वारा बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए था। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सचेतक मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह नोटिस सौंपा। नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

मेडिकल सीटें खाली न रहें, इसलिए पात्रता अर्हता प्रतिशत को कम किया गया : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उन्होंने कहा कि अर्हता प्रतिशत में संशोधित का निर्णय एमसीसी द्वारा दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद लिया गया है जिसमें यह सूचित किया गया है कि एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तावित 29,476 सीटों में से 9,621 सीटें रिक्त रह गई थीं।

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले शैक्षणिक वर्षों की तरह, जिनमें सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में सफलता मिली थी, सरकार ने पीजी काउंसलिंग 2025 के लिए पात्रता अर्हता प्रतिशत को कम कर दिया ताकि बहुमूल्य पीजी मेडिकल सीटें खाली न रहें। परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित नीट पीजी काउंसलिंग में अखिल भारतीय कोटा की 50 प्रतिशत सीटें और देश भर के केंद्रीय/मानित विश्वविद्यालयों की 100 प्रतिशत सीटें शामिल होती हैं।

उन्होंने कहा कि अर्हता प्रतिशत में संशोधित का निर्णय एमसीसी द्वारा दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद लिया गया है जिसमें यह सूचित किया गया है कि एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तावित 29,476 सीटों में से 9,621 सीटें रिक्त रह गई थीं। मंत्री ने कहा कि चूंकि 50 प्रतिशत सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि दो दौर के बाद लगभग 20,000 सीटें रिक्त रह गई।

उन्होंने कहा, अतः उन पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्षों जो सीटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रभावकारी सिद्ध हुए, के अनुरूप सरकार ने पीजी काउंसलिंग हेतु पात्रता के लिए अर्हता प्रतिशत को कम कर दिया ताकि महत्वपूर्ण पीजी सीटें खाली न रह जाएं।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत ने पांच पायदान की छलांग लगाई

नई दिल्ली/भाषा। भारत मंगलवार को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2025 में 182 देशों और क्षेत्रों में से पांच पायदान ऊपर चढ़कर 91वें स्थान पर पहुंच गया। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के नवीनतम सीपीआई के अनुसार, भारत का स्कोर पिछले वर्ष से एक अंक बढ़ गया है, जबकि इसकी रैंक 96वें स्थान से बेहतर हुई है। बर्लिन स्थित भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार-रोधी प्रगति धीमी है, क्योंकि पिछले साल कई देशों में जनता का रोष देखा गया। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' ने कहा कि 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से पता चलता है कि दुनिया के हर हिस्से में भ्रष्टाचार एक गंभीर खतरा बना हुआ है, हालांकि प्रगति के सीमित संकेत हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, नेताओं को सत्ता के दुरुपयोग और इस गिरावट के लिए जिम्मेदार व्यापक कारकों, जैसे लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन को वापस लेना और नागरिक समाज पर हमलों से निपटने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

इसमें कहा गया, ''दुनिया के कई हिस्सों में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों से पता चलता है कि लोग गैर-जिम्मेदार नेतृत्व से तंग आ चुके हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं।'' सीपीआई दुनिया भर के 182 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर रैंक देती है। परिणाम शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत स्वच्छ) के पैमाने पर दिए गए हैं।

एआई से तैयार डीपफेक सामग्री पर सरकार ने सख्त किए नियम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को डीपफेक सहित एआई (कृत्रिम मेधा) से तैयार और बनावटी सामग्री के प्रबंधन को लेकर ऑनलाइन मंचों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को किसी सक्षम अधिकारी या अदालतों द्वारा निर्देशित की गई ऐसी किसी भी सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इसके जरिये औपचारिक रूप से एआई से तैयार और बनावटी कटेंट को परिभाषित किया गया है। ये नए नियम 20 फरवरी, 2026 से लागू होंगे।

संशोधनों में ध्वनि, दृश्य या ध्वनि-दृश्य 'जानकारी' और बनावटी रूप से तैयार की गई 'जानकारी' को परिभाषित किया गया है, जिसमें एआई द्वारा निर्मित या परिवर्तित ऐसी सामग्री शामिल है जो वास्तविक या प्रामाणिक प्रतीत होती है। सामान्य संपादन, किसी सामग्री को बेहतर बनाने और नेक नीयत से किए गए शैक्षिक या डिजाइन कार्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने अधिसूचना में कहा कि प्रमुख परिवर्तनों में बनावटी सामग्री को सूचना' के रूप में मानना शामिल है। आईटी नियमों के तहत गैरकानूनी कार्यों के निर्धारण के लिए एआई-जनित सामग्री को अन्य सूचनाओं के समान माना जाएगा। सोशल मीडिया मंच को सरकारी या अदालती आदेशों पर अब 36 घंटे के बजाय तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, उपयोगकर्ता की शिकायतों के निवारण की समयसीमा भी कम कर दी गई है। नियमों के तहत एआई सामग्री की अनिवार्य रूप से लेबलिंग जरूरी है। बनावटी सामग्री बनाने या साझा करने की सुविधा देने वाले मंच को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सामग्री पर स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से लेबल लगाया जाए। जहां तकनीकी रूप से संभव हो, वहां इसे स्थायी मेटाडेटा या पहचानकर्ताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज) एक बार एआई लेबल या मेटाडेटा लगाए जाने के बाद उन्हें हटाने या छिपाने की अनुमति नहीं दे सकते।

भाजपा सांसद की 'मिनी पाकिस्तान' संबंधी टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में हंगामा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में मंगलवार को भाजपा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कोलकाता बंदरगाह की भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर के महापौर ने सार्वजनिक रूप से उस क्षेत्र को 'मिनी पाकिस्तान' कहा है। उनके इस बयान पर सदन में हंगामा होने लगा।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने स्वीकार किया कि कोलकाता बंदरगाह की भूमि का एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों के कब्जे में है और वह भूमि वापस लेने में बंदरगाह को कठिनाई हो रही है।

तृणमूल सदस्यों ने भट्टाचार्य द्वारा क्षेत्र को 'मिनी पाकिस्तान' कहने पर आपत्ति जताई और सदन में हंगामा करने लगे। प्रश्नकाल में अपना पूरक प्रश्न पूछते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता बंदरगाह लगभग 4,000 एकड़ भूमि के साथ कोलकाता शहर का सबसे बड़ा भूस्वामी है।

उन्होंने कहा कि बंदरगाह की लगभग 170 एकड़ भूमि अवैध कब्जे में है। भाजपा सदस्य ने कहा, इस अतिक्रमण का एक बड़ा हिस्सा गार्डन रीच, मटियाबुर्ज और खिदिरपुर क्षेत्र में स्थित है, जिसे

कोलकाता के महापौर ने सार्वजनिक रूप से 'मिनी पाकिस्तान' कहा है। उनकी इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शेम, शेम के नारे लगाए। उन्होंने कहा, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वह भारतीय रेलवे की जमीन हो, चाहे बंदरगाह की जमीन हो, चाहे डीवीसी की जमीन हो, या फरक्का बैराज... हर जगह अतिक्रमण हो रहा है। कोलकाता के महापौर सार्वजनिक रूप से 'मिनी पाकिस्तान' कह रहे हैं, वे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनके सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा, सांसद ने जो कहा वह सही है... वहां लोगों ने हर जगह अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन, हमारे बंदरगाह प्राधिकरण ने इस जमीन को खाली कराने के लिए अदालत में मामला दायर किया है।

तृणमूल सदस्यों के कड़े विरोध के बीच मंत्री ने कहा, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है और हम उस जमीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं। ठाकुर ने कहा, यह सच है कि मेयर ने मीडिया के सामने 'मिनी पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे पास दस्तावेज़ है, हम उसे दिखा सकते हैं।'' जब सभापति सी पी राधाकृष्णन ने राकांपा (एसपी) सदस्य फौजिया खान से अपना पूरक प्रश्न पूछने को कहा, तो उन्होंने रिकॉर्ड से 'मिनी पाकिस्तान' शब्द हटाने का आग्रह किया। इस पर सभापति ने उनसे अपनी बात रखने को कहा। बाद में, माकपा के जॉन ब्रिटास ने कहा कि अगर भट्टाचार्य उसे 'मिनी पाकिस्तान' कहते हैं, तो पाकिस्तान उस क्षेत्र की मांग कर सकता है। इस पर आसन ने उनसे अपना पूरक सवाल पूछने को कहा।

चंद्रबाबू नायडू ने वैष्णव से मुलाकात की, आंध्र प्रदेश के लिए की कई मांगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रेल मंत्री से दक्षिण तटीय रेलवे जोन में एक अप्रैल से परिचालन शुरू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने का भी किया आग्रह

नई दिल्ली/अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को यहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और राज्य में चल रही रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने, नई रेलवे लाइनों को मंजूरी देने और अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आंध्र प्रदेश सरकार के एक प्रेस बयान में कहा गया है, बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने हाल में पेश किए गए केंद्रीय बजट में घोषित उच्च गति रेल गलियारे का जिक्र किया, जिनमें हैदराबाद–बेंगलूरु, हैदराबाद–चेन्नई और चेन्नई–बेंगलूरु कॉरिडोर शामिल हैं। इसमें कहा गया है, उन्होंने आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले तीन उच्च गति रेल गलियारों की घोषणा करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

नायडू ने अनुरोध किया कि बेंगलूरु–चेन्नई उच्च गति रेल गलियार को तिरुपति से जोड़ने के लिए विस्तारित किया जाए, जिससे इस प्रमुख तीर्थ शहर से कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। अधिकारियों ने बताया कि नायडू ने रेल मंत्री से दक्षिण तटीय रेलवे जोन में एक अप्रैल से परिचालन शुरू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया।

बयान में कहा गया है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच माल ढुलाई को बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने इटारसी और विजयवाड़ा के बीच एक समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने विजयवाड़ा होते हुए खड़गपुर और चेन्नई के बीच पूर्वी तट माल ढुलाई गलियारे का भी प्रस्ताव रखा, जो आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री ने रायलसीमा और आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए कई नई रेलवे लाइनों के प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया।

अजित पवार विमान हादसा : रोहित पवार ने साजिश की आशंका जताई, विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पिछले माह हुए उस विमान हादसे में साजिश का संदेह है जिसमें उनके चाचा एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गयी थी।

उन्होंने विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा इस हादसे की विस्तृत जांच की मांग भी की। राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार ने, हालांकि, इस त्रासदी में किसी भी साजिश की आशंका को खारिज करते हुए इसे एक दुर्घटना करार दिया था। रोहित पवार ने एक संवददाता सम्मेलन के दौरान विमान की कमान संभाल रहे कैप्टन सुमित कपूर के पिछले रिकॉर्ड पर सवाल उठाया और अतीत में शराब के सेवन के लिए उनके तीन साल के निलंबन का हवाला भी दिया।

उन्होंने कहा कि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के पास इस हादसे की पूरी जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच कराये जाने की मांग भी की, जिनमें भारतीय एजेंसियों के अलावा राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, नागरिक विमानन सुरक्षा जांच एवं विश्लेषण ब्यूरो, ब्रिटेन की विमान दुर्घटना जांच शाखा (एएआईबी) शामिल हों। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त लियरजेट विमान की मालिकाना कंपनी वीएसआर' का डीजीसीए के अधिकारियों पर प्रभाव है और वह कुछ भी करके बच सकती है। रोहित पवार ने कहा कि वीएसआर कंपनी के एक विमान के 2023 में हुए हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी गई है। इसके बावजूद, वीएसआर कंपनी के विमान अब भी उच्चस्तरीय नेताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कंपनी का परिचालन लाइसेंस कभी क्यों रद्द नहीं किया गया।

रोहित पवार ने कहा कि बुकिंग करने वाली कंपनी एरो, वीएसआर कंपनी और पायलट सुमित कपूर पर गंभीर संदेह हैं। उन्होंने आरोप लगाया, हमें नहीं लगता कि यह महज एक दुर्घटना थी। ''इसमें साजिश की बू है।'' रोहित पवार ने दुर्घटना से पहले के घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या अंतिम क्षणों से पहले विमान का ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद कर दिया गया था?

रोहित पवार के अनुसार, मूल पायलट –साहिल मदान और यश–कथित तौर पर यातायात के कारण देरी से पहुंचे थे। उन्होंने पूछा, तो सुमित कपूर और शांभवी पाठक हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचे? क्या वे आसपास ही रहते थे? उन्होंने यह भी कहा कि पाठक को कपूर की तुलना में लियरजेट उड़ाने का अधिक अनुभव था। उन्होंने दावा किया कि विमान के एक तरफ झुकने पर कपूर चुप रहे। राकांपा (शप) विधायक ने पूछा, उन्होंने (कपूर ने) मुश्किल रनवे 11 की मांग क्यों की और दृश्यता की समस्या के बावजूद लैंडिंग का प्रयास क्यों किया?

तेलंगाना में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना पुलिस ने 11 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तौर पर संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी शिवधर रेड्डी ने यहां पत्रकारों को बताया कि सात नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 8,203 मतदान केंद्रों में से 1,302 को 'अति संवेदनशील' और 1,926 को 'संवेदनशील' की श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

रेड्डी ने कहा, 'पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है और हमें विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे।' उन्होंने यह भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों के भीतर और अति संवेदनशील केंद्रों के बाहर शत–प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित की गई है। वेबकास्टिंग का मतलब मतदान और चुनावी गतिविधियों का ऑनलाइन सीधा प्रसारण होता है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1,183 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं और 4,318 लोगों को पाबंद किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 142 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार अभियान सोमवार शाम को समाप्त हो गया।

राकांपा के दोनों गुटों के नेता लेंगे विलय पर फैसला: फडणवीस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के नेता विलय के मुद्दे को सुलझाएंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस पर तभी टिप्पणी करेगी, जब कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पिछले महीने राकांपा प्रमुख एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा, ''हमने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और सुनेत्रा पवार का स्वागत किया। उनके (सुनेत्रा के) नेतृत्व में राकांपा ने जिला परिषद चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। राकांपा के दोनों गुटों के विलय का निर्णय संबंधित दलों को लेना है। भाजपा इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया (विलय के) फैसले के बाद देगी।'' पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और उन्होंने आवंटित विभागों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अजित पवार की मृत्यु के बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) के नेताओं ने दावा किया था कि दोनों गुटों के विलय को लेकर वार्ता काफी आगे पहुंच गयी थी और इसकी घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली गई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भगवत के बारे में की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, फडणवीस ने कहा कि संघ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए गए लोग बुरा मान रहे हैं और आलोचना का सहारा ले रहे हैं।

राज ठाकरे ने भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अगर संघ प्रमुख को लगता है कि अपनी भाषा के लिए विरोध करना 'एक बीमारी' है तो देश के अधिकांश राज्य इससे पीड़ित हैं। फडणवीस ने कहा, जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, वे नाराज हैं, इसलिए वह (ठाकरे) आलोचना का सहारा ले रहे हैं। आरएसएस का कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को 100 वर्ष पूरा कर चुके इस संगठन के बारे में जानकारी देने और उनसे संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। जिन लोगों को निमंत्रण नहीं मिला, वे नाराज हैं। चंद्रपुर में भाजपा द्वारा शिवसेना (उबाठा) के समर्थन से कांग्रेस को मात देकर महापौर पद जीतने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर बात करेंगे।

निर्वाचन आयोग ने पांच विधानसभा चुनावों से पहले गृह जिले में जमे अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया

नई दिल्ली/भाषा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग (ईसी) ने संबंधित सरकारों से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने को कहा है, जो चुनावों से पहले उठाया जाने वाला एक नियमित कदम है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संचालन से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए जहां उन्होंने काफी लंबे समय तक सेवा की हो। आयोग ने बताया कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग–अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है ताकि वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक नई विधानसभा का गठन हो सके। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव से सीधे संबद्ध नहीं रहने वाले सरकारी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रधानाचार्य को चुनाव वाले राज्यों के संबंध में ईसी की स्थानांतरण नीति से छूट दी गई है।

गोवा के समुद्र तट पर रूसी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा के बागा बीच पर कुछ रूसी महिला पर्यटकों के साथ कथित तौर पर कुछ पुरुषों ने छेड़छाड़ की। हालांकि, बीच मार्शल और एक जीवन रक्षक के समय पर हस्तक्षेप से मामला और बिगड़ने से बच गया।

पिछले सप्ताह हुई इस घटना में शामिल घरेलू पर्यटकों को चेतावनी देकर वहां से जाने की अनुमति दे दी गई थी। बीच सेफ्टी एजेंसी, दृष्टि मरीन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि पिछले सप्ताह गोवा के समुद्र तट पर महिला पर्यटकों से जुड़े उत्पीड़न के चार मामले, तीन चिकित्सा आपात स्थिति और एक गुमशुदा वस्तु मिलने का मामला दर्ज किया गया।

एक अन्य घटना में तेलंगाना के दो पुरुष पर्यटकों ने कथित तौर पर शराब के नशे में समुद्र तट के पास सेल्फी लेने से इनकार करने पर एक विदेशी महिला को परेशान किया। आरोप है कि उनमें से एक व्यक्ति ने महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसे चूमने की कोशिश की। दोनों पर्यटकों को थाने ले जाया गया। वर्तमान में लगभग 70 मार्शल पांच लोकप्रिय समुद्र तटों (बागा, कलांगुट, कैंडोलिम, कोल्वा और बेनौलिम) पर तैनात हैं।

दक्षिण गोवा के कोल्वा बीच पर कर्नाटक के सात, आठ पर्यटकों का एक समूह बिना सहमति के कथित तौर पर रूसी महिलाओं के वीडियो बना रहा था और उनकी तस्वीरें खींच रहा था।

जीवन रक्षकों ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई के लिए उन लोगों को गोवा पुलिस के हवाले कर दिया। रविवार शाम को पटनेम बीच पर जीवन रक्षकों ने देखा कि बिहार के पांच पर्यटक कथित तौर पर पुणे के एक दंपति को परेशान कर रहे थे और उनकी सहमति के बिना उनका वीडियो बना रहे थे।

दंपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और गोवा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिसकर्मी 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे और पर्यटकों को कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया।

लैंबॉर्गिनी हादसा : वकील ने शिवम के गाड़ी न चलाने का दावा किया, पुलिस ने इसे नकारा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कानपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैंबॉर्गिनी से छह लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के अधिवक्ता ने दावा किया है कि घटना के समय शिवम कार नहीं चला रहा था, जबकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान व अन्य सबूतों से यह स्पष्ट है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। शिवम के वकील मृत्युंजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि गाड़ी शिवम के परिवार का चालक मोहन चला रहा था, न कि शिवम।

कानपुर के पॉश ग्वालटोली इलाके में वीआईपी रोड' पर अपराह्न करीब सवा तीन बजे 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कार लैंबॉर्गिनी ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को कुचल दिया था। इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए थे। अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा, कार परिवार का चालक चला रहा था, न कि शिवम मिश्रा। हम अदालत के समक्ष तथ्य और साक्ष्य पेश करेंगे।

उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि इस मामले को उनके मुवक्किल के खिलाफ सीधे आपराधिक कृत्य के बजाय एक दुर्घटना के रूप में देखा जाए। हालांकि, कानपुर पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अब तक की जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पीटीआई–भाषा' को बताया कि उपलब्ध सबूत और चश्मदीदों के बयान शिवम मिश्रा के गाड़ी

चलाने की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा, कभी–कभी प्राथमिकी में शुरुआत में गलत या अधूरी जानकारी हो सकती है। जांच के दौरान सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से शिवम मिश्रा की संलिप्तता की पुष्टि हुई है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके के वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें टक्कर के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग और बचावकर्मी को एक व्यक्ति को चालक की सीट से बाहर खींचते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वह शिवम मिश्रा ही है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मौके के सीसीटीवी फुटेज से भी पहचान की हुई है कि कार से बाहर निकाला गया व्यक्ति शिवम मिश्रा ही था। उन्होंने कहा कि वकील की दलीलों से जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डीसीपी ने कहा, कोई भी वकील अदालत में जो दलील देता है, उससे हमारी जांच प्रभावित नहीं होती। यदि अदालत किसी स्पष्टीकरण की मांग करती है, तो सभी तथ्य उसके समक्ष रखे जाएंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम नोटिस देने के लिए आर्य नगर स्थित शिवम मिश्रा के घर भी गई थीं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। प्राथमिकी में शुरुआत में लैंबॉर्गिनी कार के अज्ञात चालक का उल्लेख था, लेकिन बाद में इसमें शिवम मिश्रा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया। कार को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस बीच, मंगलवार को आरोपी शिवम मिश्रा के पिता तंबाकू कारोबारी के.के. मिश्रा ग्वालटोली पुलिस थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके बेटे को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।

पुलिस थाने के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए के.के. मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि दुर्घटना के समय उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था।

उन्होंने कहा, मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। वह सो रहा था। हमारा चालक मोहन गाड़ी चला रहा था। उन्होंने बताया कि शिवम की तबीयत खराब है और वह फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। शिवम के पिता ने आश्वासन दिया कि वह और उनका बेटा दोनों जांच में सहयोग करेंगे और कहा कि स्वास्थ्य में सुधार होने पर शिवम पुलिस की पूछताछ में शामिल होगा।

तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं में देरी के लिए द्रमुक सरकार जिम्मेदार : श्रीनिवासन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं में कथित देरी को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि राज्य स्तर की देरी के कारण विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए।

कोयंबटूर दक्षिण से विधायक श्रीनिवासन ने भूमि अधिग्रहण में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को योजनाओं का तेजी से लाभ मिलना चाहिए। उनकी यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा कुछ दिन पहले लगाए गए इस आरोप के बाद आई है कि केंद्र ने केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को उसके हिस्से की रेलवे परियोजनाएं नहीं दीं और बाद में देरी के लिए राज्य सरकार पर ही दोष मढ़ दिया।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्रीनिवासन ने कहा, 2014 से केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए 7,611 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद द्रमुक सरकार की धीमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण प्रगति रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि आवश्यक 4,326 हेक्टेयर भूमि में से अब तक केवल 1,052 हेक्टेयर का ही अधिग्रहण किया जा सका है।

उन्होंने कहा, राज्य स्तर की देरी के कारण विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन होना चाहिए। राज्य सरकार पर रेलवे परियोजनाओं के मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए तमिलनाडु की रेलवे परियोजनाओं के लिए किया गया आवंटन 2014 की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने दावा किया कि राज्य में जारी रेलवे परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार अब तक केवल 24 प्रतिशत भूमि का ही अधिग्रहण कर पाई है और 4,326 हेक्टेयर की आवश्यकता के मुकाबले केवल 1,052 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध कराई गई है।

श्रीनिवासन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र ने तमिलनाडु सरकार को 1,465 करोड़ रुपये जारी किए थे और रेलवे परियोजनाओं के अमल में देरी का कारण यह है कि राज्य सरकार आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की है।

शबरीमला ध्वज स्तंभ : टीडीबी के पूर्व सदस्य बोले- सोने के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि/भाषा। कांग्रेस नेता और त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व सदस्य अजय थरायिल ने मंगलवार को कहा कि 2017 में शबरीमला मंदिर में नए ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में श्रद्धालुओं से प्राप्त सोने के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नए ध्वज स्तंभ का काम उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया था और इस संबंध में सभी खाते अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

थरायिल का यह स्पष्टीकरण तब आया है जब केरल उच्च न्यायालय ने सतर्कता विभाग को 2017 में शबरिमला मंदिर में नए ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में सोने और धन के कथित दुरुपयोग की जांच करने का आदेश दिया है। शबरिमला द्वारपाल (संरक्षक देवता) की प्लेटों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के द्वार से कथित तौर पर सोने की चोरी के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया।

यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए थरायिल ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी सहित विभिन्न श्रद्धालुओं से अतिरिक्त दान के रूप में 412 ग्राम सोना प्राप्त हुआ, इसके अलावा 22 मार्च, 2017 को सीमा शुल्क विभाग से 9.161 किलोग्राम सोना खरीदा गया था। पंबा में नए ध्वज स्तंभ का संपूर्ण कार्य अधिवक्ता आयुक्त, तिरुवाभरणम आयुक्त, देवस्वओम सतर्कता अधिकारी आदि की देखरेख में संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में इस्तेमाल किए गए सोने का पूरा हिसाब तिरुवाभरणम आयुक्त द्वारा टीडीबी सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

थरायिल ने कहा, महासार में सब कुछ दर्ज है। उन्हें बताना चाहिए कि इस संबंध में अतिरिक्त सोना कहां से प्राप्त हुआ था। ये आंकड़े सटीक थे और टीडीबी द्वारा प्रमाणित किए गए थे। इसे उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने एसआईटी की आलोचना करते हुए उस पर जानबूझकर उच्च न्यायालय में गलतफहमी पैदा करने का आरोप लगाया। हालांकि, थरायिल ने सतर्कता विभाग को आरोपों की त्वरित जांच करने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। थरायिल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक नेता ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने इसे एक राजनीतिक चाल बताते हुए कहा कि वह इसका विरोध करेंगे। उन्होंने ने एलडीएफ सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी यूडीएफ नेताओं को भी शबरिमला में सोने की चोरी के मामले में शामिल दिखाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के वरिष्ठ नेता एवं नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी।

यह मुलाकात द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की उप महासचिव कनिमोई द्वारा हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के तुरंत बाद और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी की मांग के मद्देनजर हो रही है। हालांकि, टीएनसीसी प्रमुख के. सेल्वापेरुंथगई ने स्पष्ट किया कि द्रमुक के साथ संबंधों में कोई दरार नहीं है और गठबंधन एवं सीट का बंटवारा कांग्रेस नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा। जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आने को कहा गया है। यहां एक सूत्र ने बताया कि राहुल संभवतः उनसे और राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे।

द्रमुक एक बार फिर सत्ता में आएगी, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी, सत्ता बरकरार रखेगी और जनता की शेष मांगों को पूरा करेगी।

स्टालिन ने यहां एक कार्यक्रम में विधायक एस इनिगो इरुदयाराज की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ मांगों को पूरा किया जाना अभी बाकी है। वह ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर क्रिश्चियन हायर एजुकेशन और वुमंस क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। इरुदयाराज तिरुचिरापल्ली-पूर्वी से द्रमुक के विधायक हैं, और क्रिस्टुवा नल्लेन्ना इयक्कम (ईसाई सद्भावना आंदोलन) का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्टालिन ने याद दिलाया कि क्रिसमस के कार्यक्रमों में, उन्होंने दिसंबर 2025 में तिरुनेलवेली में कई मांगों को पूरा करने की घोषणाएं की थीं। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रमुक एक बार फिर सत्ता में आएगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी मजदूर पर हमले के मामले में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तमिलनाडु के तिरुतानी रेलवे क्वार्टर के पास चार किशोरों द्वारा एक प्रवासी मजदूर पर कथित रूप से हमला किए जाने के लगभग एक महीने बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें पीड़ित का ''जल्द से जल्द पता'' लगाने और उसे आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने को कहा गया है।

एनएचआरसी ने नोटिस में यह भी पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। पीड़ित की पहचान सूरज नामक प्रवासी मजदूर के रूप में की गई है।

तमिलनाडु पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय चार किशोरों को 28 दिसंबर को पकड़ कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। बोर्ड के आदेशानुसार, तीन को किशोर गृह भेजा गया और चौथे को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। नौ फरवरी के नोटिस में कहा गया, ''28 दिसंबर को तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल ने पीड़ित को बेहतर चिकित्सा के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल रेफर किया था। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार, यह पाया गया कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद पीड़ित उसी दिन अस्पताल से चला गया।'' आयोग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में मध्यप्रदेश के एक प्रवासी मजदूर के साथ हुई ''गंभीर हिंसा'' की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो और पुलिस खुलासों के अनुसार, पीड़ित को चलती ट्रेन में धमकाया गया था।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़ित को जबरन रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर ले जाकर उस पर चार नाबालिगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले का वीडियो भी बनाया गया जिसमें एक हमलावर विजय चिन्ह' दिखाता नजर आया। एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत लिया है। शिकायतकर्ता ने आयोग से स्वतंत्र जांच, सख्त कानूनी कार्रवाई, पीड़ित के लिए मुआवजा और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की मांग की। पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा सुविधा में भेजा गया, लेकिन वह चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद अस्पताल से चला गया और अब तक उसका पता नहीं चल सका है।

आयोग ने कहा कि यह राज्य तंत्र की गंभीर चूक और घोर लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि पीड़ित को पर्याप्त सुरक्षा, निगरानी या सहायता नहीं मिली। तमिलनाडु सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को सात दिन में जवाब देने का निर्देश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि उन्हें पीड़ित को सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार, परामर्श आदि उपलब्ध कराना होगा। एनएचआरसी ने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया कि पीड़ित का जल्द पता लगाकर उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।

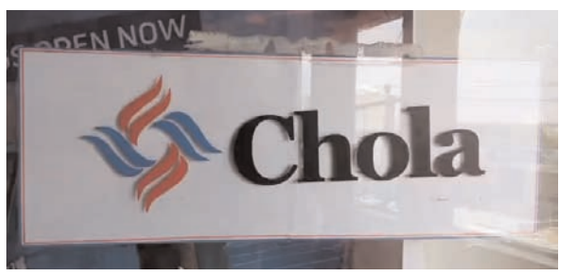

चोलामंडलम फाइनेंशियल का तीसरी तिमाही का मुनाफा 27 प्रतिशत बढ़कर 1,386 करोड़ रुपये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। मुरुगप्पा समूह की कंपनी चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (सीएफएचएल) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 27 प्रतिशत बढ़कर 1,386 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में शुद्ध लाभ 1,093 करोड़ रुपये रहा था।

चेन्नई मुख्यालय वाली इस कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में उसकी कुल आय 17 प्रतिशत बढ़कर 10,084 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,593 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीने की अवधि के लिए उसका शुद्ध लाभ 14 प्रतिशत बढ़कर 3,860 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,378 करोड़ रुपये था। इसी अवधि (अप्रैल-दिसंबर) में कुल आय 19 प्रतिशत बढ़कर 29,056 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 24,451 करोड़ रुपये थी।

अनुषंगी कंपनियों के प्रदर्शन के बारे में कंपनी ने कहा कि सामान्य बीमा व्यवसाय से जुड़ी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 'सकल रिटर्न प्रीमियम' (जीडब्ल्यूपी) तीसरी तिमाही में 2,361 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 2,175 करोड़ रुपये था। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें सीएफएचएल की 44.18 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने समीक्षाधीन तिमाही के दौरान 29,962 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 25,806 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने बताया कि उसके संयुक्त उद्यम चोलामंडलम एमएस रिस्क सर्विसेज लिमिटेड की कुल आय तीसरी तिमाही में बढ़कर 26.47 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में 21.46 करोड़ रुपये थी।

विजय की फिल्म 'जन नायकन' के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपनी याचिका वापस ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता-नेता विजय अभिनीत तमिल फिल्म 'जन नायकन' के निर्माताओं को उनकी वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। यह याचिका न्यायमूर्ति पी. टी. आशा के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी और उन्होंने फिल्म के निर्माता मेसर्स केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने ''याचिका को वापस ली गई'' मानते हुए खारिज कर दिया। निर्माता कंपनी 'केवीएन प्रोडक्शन' ने पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को पत्र लिखकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ मामला वापस लेने के अपने इरादे से अवगत करा दिया था।

इससे पहले, नौ जनवरी को न्यायमूर्ति आशा ने केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीएफसी को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने पांच जनवरी को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भेजे गए उस पत्र को भी रद्द कर दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष ने मामले को पुनरीक्षण समिति (रिवाइजिंग कमेटी) को भेज दिया है। हालांकि, उसी दिन मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने सीबीएफसी द्वारा दायर अपील पर एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 20 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने 27 जनवरी को अपील स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म को तत्काल सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, पीठ ने याचिका को खारिज करने के बजाय फिल्म निर्माताओं को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने का अवसर दिया और इसे मूल रिकॉर्ड में बहाल कर दिया।

मामले के अनुसार, 22 दिसंबर को निर्माताओं को चेन्नई स्थित क्षेत्रीय अधिकारी से सूचना मिली थी कि पांच सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म देखने के बाद इसके प्रदर्शन और सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की है। इसके बाद जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष ने 22 दिसंबर के पत्र को रोकते हुए मामले को पुनरीक्षण समिति को भेजने का निर्णय लिया, जिसकी जानकारी पांच जनवरी को फिल्म निर्माताओं को दी गई थी।

मोदी सरकार में अनेक योजनाओं की घोषणा, लेकिन क्रियान्वयन नहीं : कार्ति चिदंबरम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चिंदबरम ने लोकसभा में कहा कि वित्त मंत्री को सदन में अपने जवाब में इस बारे में स्थिति करनी चाहिए स्पष्ट

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में बजट में अनेक योजनाएं घोषित करने लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण लोगों की रुचि बजट को लेकर कम हो रही है।

कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बजट में बड़ी संख्या में योजनाओं की घोषणा की है लेकिन उनके क्रियान्वयन की स्थिति बहुत कमजोर है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सदन में अपने जवाब में इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों की कम उपस्थिति का दावा करते हुए कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ही जनता और सांसदों की रुचि बजट में घट रही है।

कार्ति ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या हम रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेंगे'' और क्या भारत, अमेरिका के कृषि उत्पाद शून्य शुल्क पर खरीदने की अनुमति देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात करने वाली मोदी सरकार ने बजट में सशस्त्र बलों की दिव्यांगता पेंशन को आयकर के दायरे में लाने का गलत निर्णय लिया और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

वहीं, भाजपा की डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच बजट में ठोस कदम उठाए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के ही जगदीश शेट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले अनेक बजट में कर्नाटक के लिए कई राजमार्गों और रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि केवल प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना करते रहते हैं।

वाईएसआर कांग्रेस के वाई एस अविनाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग दोहराई। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने बजट को आंकड़ों की बाजीगारी'' करार देते हुए कहा कि इसमें समाधानों की बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष के नौ महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद 41 प्रतिशत से अधिक बजट खर्च नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गरीबी उन्मूलन चाहती है तो उसे बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले) लोगों से जीएसटी लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को जीएसटी से छूट का एक कार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) बढ़ाने की भी मांग की।

ईडी ने तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले में धनशोधन का प्रकरण दर्ज किया

अमरावती/नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में 'लड्डू प्रसादम' बनाने के लिए कथित रूप से मिलावटी घी के इस्तेमाल से जुड़े मामले की जांच के लिए धन शोधन का प्रकरण दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने कुछ समय पहले आरोपी द्वारा कथित रूप से अर्जित अपराध की आय या अवैध धन की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी द्वारा दर्ज प्राथमिकी, दस्तावेजों और हाल में दायर आरोपपत्र को देख रही है। एसआईटी ने इस मामले में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के नौ अधिकारियों और पांच डेयरी विशेषज्ञों सहित 36 लोगों को आरोपी बनाया है। एसआईटी की जांच के निष्कर्षों के अनुसार, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर निकाय को घी के रूप में बेची गई मूल सामग्री रासायनिक रूप से संसाधित पामोलिन तेल और अन्य अवयवों से बनी थी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किए गए धनशोधन और घी में मिलावट के माध्यम से अवैध धन उत्पन्न करने की संभावना की जांच कर रही है।

यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए केरल में रेलवे की दो परियोजनाओं को मंजूरी : गोपी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे की दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिससे राज्य के लोगों की रेल यात्रा संबंधी परेशानियां कम होंगी और माल की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि अलाप्पुझा-अंबलप्पुझा लाइन और पलक्कड़ शहर-पराली बाईपास लाइन के दोहरीकरण की ये दोनों परियोजनाएं केरल के विकास को बढ़ावा देंगी।

मंत्री ने 'फेसबुक' पर एक पोस्ट में कहा कि 12.66 किलोमीटर लंबी अलाप्पुझा-अंबलप्पुझा लाइन के दोहरीकरण के लिए 324.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना एर्नाकुलम-थुरवूर-कायमकुलम मार्ग पर यातायात की बाधा को दूर करने में मदद करेगी। गोपी ने कहा कि 1.8 किलोमीटर लंबी पलक्कड़ शहर-पराली बाईपास लाइन के लिए 163.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे पलक्कड़ जंक्शन पर ट्रेन के इंजन बदलने के कारण लगने वाला प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यात्री ट्रेन का यात्रा समय 40-44 मिनट और मालगाड़ियों का यात्रा समय 120 मिनट तक कम हो जाएगा।

संतों की शिक्षा को आत्मसात करे युवा पीढ़ी : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के आराध्य गोविंददेव जी मंदिर परिसर स्थित जय निवास उद्यान से विधिवत पूजा-अर्चना कर विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत-महात्मा राष्ट्र को सही दिशा देकर सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं तथा इनके विचार मानवता, सेवा एवं सद्भावना का संदेश देते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करें तथा भारत की गौरवाशाली परम्परा को आगे बढ़ाने में योगदान दें।शर्मा ने कहा कि बाबा बालनाथ ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया। इसी परंपरा का बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की अवधारणा पर आधारित है, जो सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश देती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तीनाथ महाराज को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान शर्मा ने महाराज जी के आशीर्वचन भी सुनें। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इससे पहले शर्मा ने गोविंददेव जी मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंददेव जी के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत सहित गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर शादी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर महिला से शादी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अक्षत कोठारी के रूप में हुई है। वह लंबे समय से फरार था और उसे मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षत ने सोशल मीडिया मंच पर फोटो और गलत जानकारी अपलोड करके खुद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का अधिकारी बताया। पुलिस ने कहा कि इसी फर्जी पहचान के आधार पर उसने कथित तौर पर एक महिला से शादी कर ली। महिला ने बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बांसवाड़ा की साइबर पुलिस टीम आरोपी को इंदौर से पकड़कर लाई और उससे पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा के साइबर पुलिस थाने के निरीक्षक हरिओम ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहता था। उन्होंने बताया, आरोपी जगह बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। हमने उसे पकड़ने से पहले करीब 24 घंटे तक कड़ी निगरानी रखी। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर धोखाधड़ी के हैं।

जयपुर से दो जापानी पर्यटक लापता

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में घूमने आए दो जापानी पर्यटकों के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अशोक नगर के थाना प्रभारी मोती लाल शर्मा ने बताया कि इन पर्यटकों द्वारा किराए पर ली गई टैक्सी के चालक ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों पुरुष पर्यटक नयी दिल्ली से जयपुर आए थे और सात फरवरी को एक होटल में रुके। टैक्सी का चालक दोनों पर्यटकों को शनिवार रात अशोक नगर थाना क्षेत्र के एक रेस्तरां ले गया लेकिन वे टैक्सी में वापस नहीं आए। उन्होंने कहा, चालक ने रविवार सुबह तक पर्यटकों का इंतजार किया लेकिन उन्होंने उससे संपर्क नहीं किया। वे अपने होटल भी नहीं पहुंचे जिसके बाद टैक्सी चालक ने पुलिस थाने जाकर सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के अनुसार इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

विकास पर केंद्रित रहेगा इस बार का राजस्थान बजट : बैरवा

जयपुर । राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने राज्य सरकार के बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजस्थान के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि जब राजस्थान में भाजपा सरकार बनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यभार संभाला, तब से अब तक दो बजट पेश किए जा चुके हैं। इन दोनों बजटों में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि राजस्थान को विकास की नई दिशा दी जा सके। बैरवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारकर जनता तक उसका लाभ पहुंचाना है। बता दें कि राजस्थान का बजट 11 फरवरी को पेश होना है।

वहीं पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच के बहिष्कार के फैसले से पलटने पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल के मैदान में किसी भी तरह की नकारात्मकता या राजनीतिक भावना नहीं होनी चाहिए। बैरवा ने कहा कि खेल देशों को जोड़ने का माध्यम होते हैं और इसमें आपसी सौहार्द और सकारात्मक सोच जरूरी है।

इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर भी उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है और वह हमेशा ऐसा करता रहेगा। बैरवा ने लोकसभा स्पीकर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान स्पीकर सदन को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और संसदीय मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं।

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में राजस्थान मंडप बना आकर्षण का केन्द्र

जयपुर/दक्षिण भारत। हरियाणा के सूरजकुंड, फरीदाबाद में 15 फरवरी तक आयोजित हो रहे 16 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में राजस्थान मंडप आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। मेले में राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पादों की खूब बिक्री हो रही है साथ ही राजस्थान के पर्यटन क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी आगंतुकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक छत्रपाल यादव ने बताया कि सूरजकुंड मेले में इस बार 11 फरवरी को राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह सांस्कृतिक संध्या मुख्य चौपाल मंच, सूरजकुंड मेला परिसर में सायं 6.30 बजे से प्रारंभ होगी।

उन्होंने बताया कि इस सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान की समृद्ध लोककला, लोकनृत्य एवं लोकसंगीत की विविध झलकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत खड़ताल वादन एवं गायन से होगी, जिसमें बाड़मेर के मगड़ा खां मागनियार अपनी प्रस्तुति देंगे।

यादव ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम अजमेर की सुअरूषिका द्वारा चरी नृत्य एवं घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। बूंदी के हरिशंकर नागर द्वारा कच्छी घोड़ी नृत्य दर्शकों को आकर्षित करेगा। डूंगरपुर के गफूरुद्दीन मेवाती (पद्म2026) द्वारा मृदंग वादन प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिसूचित आर्द्रभूमियों एवं रामसर स्थलों को प्राथमिकता से विकसित किया जाए

जयपुर/दक्षिण भारत। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक मंगलवार को सचिवालय में शासन सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विजय एन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कम से कम एक आर्द्रभूमि विकसित की जाए।

उन्होंने इसके लिए जिला-वार आर्द्रभूमियों की सूची तैयार कर उनका डिजिटलीकरण, नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि अलवर जिला स्थित सिलिसेढ़ झील को आदर्श आर्द्रभूमि (मॉडल वैटलैण्ड) के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए स्थानीय प्रशासन, वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पशुपालन विभाग आपसी सहभागिता से कार्य करने के लिए कहा।

शासन सचिव ने कहा कि सिलिसेढ़ झील के विकास से प्रदेश की अन्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से पर्यटन दबाव, जलग्रहण क्षेत्र का क्षरण, गाद जमाव, पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों के प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

उन्होंने प्रत्येक जिले में आर्द्रभूमि विकसित करने के एक्शन प्लान तथा आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु बजट के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों में अब तक आर्द्रभूमियाँ अधिसूचित नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजे जाएं। साथ ही जिलों में आर्द्रभूमियों की डिजिटल इन्वेंट्री समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

बैठक में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की नॉलेज पार्टनर संस्था डब्लूडब्लूएफ इंडिया द्वारा रामसर साइट सिलिसेढ़ झील (अलवर) के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में झील की भौगोलिक स्थिति, जलग्रहण क्षेत्र, जल प्रवाह व्यवस्था, जल गुणवत्ता, जलवायु आंकड़े, आर्द्रभूमि स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि सिलिसेढ़ झील सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। यह क्षेत्र की जल सुरक्षा, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झील में 149 पक्षी प्रजातियाँ, विभिन्न मछली प्रजातियाँ, स्तनधारी एवं सरीसृप पाए जाते हैं। इस प्रारूप कार्ययोजना के अनुसार सिलीसेढ़ झील के संवर्धन एवं विकास हेतु सभी संबंधित विभागों एवं हित धारकों के समन्वय से नियमानुसार कार्य किए जाएंगे।

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बीजो जॉय, वन संरक्षक वन्य जीव वन विभाग सुमोनाली सेन, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कपिल चंद्रावल, सहित पशुपालन विभाग, भू जल विभाग, स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही जिला प्रशासन- अलवर ने वीसी द्वारा भाग लिया ।

बजट आज

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 फरवरी, बुधवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया । इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया,शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे ।

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष एवं स्वस्थ संवाद जरूरी : सचिन पायलट

जयपुर/दक्षिण भारत। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष एवं स्वस्थ संवाद को जरूरी बताते हुए मंगलवार को कहा कि टकराव व दमन की मौजूदा राजनीति लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती के अवसर पर टोंक में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से आयोजित किया गया। पायलट ने कहा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं परंतु मौजूदा समय में चुनाव लड़ना...प्रतिस्पर्धा की भावना होने की बजाए नफरत में तब्दील होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति में एक-दूसरे के प्रति जो घृणा पैदा हो गई है और जो तनाव पैदा हो गया है, वह कोई शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में यदि सब दुश्मन बन जायेंगे तो सहमति कैसे बनेगी। संसद में जारी गतिरोध पर टिप्पणी करते हुए पायलट ने कहा, आज जो संसद में हो रहा है इससे सभी भली-भांति परिचित हैं। हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है कि आलोचना करना, आईना दिखाना, सवाल पूछना, मापदण्ड तय करना, जिम्मेदारी तय करना... यह विपक्ष का काम रहा है। उन्होंने कहा, मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन, आज जो टकराव एवं दमन की राजनीति उत्पन्न हो गई है, यह लोकतंत्र में सही नहीं है। समिति के कामकाज की सराहना करते हुए राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के मन में यह भाव रहता है कि गरीब, असहाय लोगों की मदद किस प्रकार से की जाये परंतु कई बार यह भावना मूर्त रूप नहीं ले पाती। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस भावना को साकार रूप प्रदान करते है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ऐसी ही एक संस्था है जिसने अनेकों अक्षम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। एक बयान के अनुसार इस तीन दिवसीय शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ-पैर, व्हीलचेयर आदि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

होली पर यात्रियों को राहत, यात्रियों की सुविधा हेतु 2 जोडी स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन

जयपुर। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे गत वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में होली के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान मे रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं-राजकोट- लालकुआं एवं गोमतीनगर-खातीपुरा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि लालकुआं-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 1 से 29 मार्च तक (05 ट्रिप) लालकुआं से प्रत्येक रविवार को दोपहर 12.35 बजे रवाना होकर सोमवार को जयपुर स्टेशन पर रात्रि 12.35 बजे आगमन व 12.45 बजे प्रस्थान कर शाम 6.10 बजे राजकोट पहुँचेगी।

इसी प्रकार राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 2 से 30 मार्च तक (05 ट्रिप) राजकोट से प्रत्येक सोमवार को रात्रि 10.30 बजे रवाना होकर मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर शाम 4.25 बजे आगमन व 4.35 बजे प्रस्थान कर बुधवार को प्रातः 5.15 बजे लालकुआं पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में किच्छा, बहेड़ी, भोजीपुरा, इज्जत नगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, बदायूं, सोरों शूकर, कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा कैंट, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, गोटन, जोधपुर, लूनी, समदड़ी, मोकलसर, जालौर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भीलडी, पाटन, महेसाना, विरमगाम, सुरेंद्रनगर व वांकानेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। उन्होंने बताया कि गोमतीनगर-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 3 से 24 मार्च तक (04 ट्रिप) गोमतीनगर से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 11.55 बजे रवाना होकर बुधवार को शाम 5.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। इसी प्रकार खातीपुरा (जयपुर) - गोमतीनगर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 4 से 25 मार्च तक (04 ट्रिप) खातीपुरा से प्रत्येक बुधवार को शाम 6.50 बजे रवाना होकर गुरूवार को प्रातः 11.45 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में बदषाहनगर, डालीगंज, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद,गाजियाबाद, दिल्ली, दिल्ली कैंट, गुडगॉव, रेवाडी, अलवर व बांदीकुई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

पशुपालन मंत्री ने पीएमविद्यालय के विद्यार्थियों को किया सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पाली जिले के पीएमराजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर का वार्षिकोत्सव एव पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समारोह में मंत्री कुमावत ने विद्यार्थियों के जीवन जीने के गुर व जीवन में माता पिता व गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने बोर्ड कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, स्थानीय परीक्षा में प्रथम आने वाले एवं विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सरस डेयरी पाली के अध्यक्ष प्रतापसिंह बिठिया सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर बोला हमला

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस ने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी ने सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरी तरह वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हैं, और भाजपा सरकार बेख़ौफ़ तमाशबीन बनी हुई है। सरकारी अस्पताल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, जाँच मशीनें महीनों से बंद हैं, दवाइयाँ नदारद हैं और मरीजों को मजबूरी में निजी लैब और मेडिकल स्टोरों की लूट सहनी पड़ रही है।

करोड़ों का बकाया होने से पेंशनर्स खाली हाथ लौट रहे हैं, इलाज की निरंतरता टूट चुकी है। यह कुप्रबंधन नहीं, बल्कि प्रशासनिक नाकामी की पराकाष्ठा है। भाजपा शासन में स्वास्थ्य सेवा जनकल्याण नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता और अव्यवस्था का शिकार बन चुकी है।

पूर्वी कमान के सेना के जवानों को वीदता पदक प्रदान किए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। मेघालय के उमरोई सैन्य केंद्र में मंगलवार को आयोजित सेना की पूर्वी कमान के वार्षिक अलंकरण समारोह में जवानों को कुल 37 वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने एक बयान में कहा कि अनुकरणीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा और विशिष्ट सेवा को लेकर आयोजित किये गये इस समारोह की अध्यक्षता पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी)' लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी ने की।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा कार्यों को मान्यता देते हुए कुल 37 वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें 19 सेना पदक (वीरता), सात सेना पदक (विशिष्ट), दो युद्ध सेवा पदक, एक विशिष्ट सेवा पदक, सात विशिष्ट सेवा पदक और एक उत्तम जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। बयान के अनुसार इसके अतिरिक्त, असाधारण पेशेवर अंदाज, परिचालन उत्कृष्टता और उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए, 49 इकाइयों और कोलकाता आर्मी पब्लिक स्कूल को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यूनिट' प्रशस्ति पदक से सम्मानित किया गया।

अधिकारी ने बताया कि समारोह में भारतीय रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी और वीर नारियों समेत पदक प्राप्तकर्ताओं के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीओसी-इन-सी ने पदक विजेताओं को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए बधाई दी और सभी कर्मियों से भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं, मूल्यों और लोकाचार को बनाए रखने' का आह्वान किया।

बयान के अनुसार, अलंकरण समारोह से पहले सोमवार को 'शौर्य संध्या' नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया और साहस एवं बलिदान की भावना का जश्न मनाया गया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की हालत में तेजी से सुधार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। सीने में संक्रमण के बाद यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराये गये राकांपा (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार तेजी से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टरों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा के 85 वर्षीय सदस्य शरद पवार ने सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें सोमवार दोपहर पुणे जिले के बारामती कस्बे स्थित उनके आवास से रूबी हॉल क्लिनिक लाया गया था। अस्पताल के चिकित्सक और न्यासी डॉ. साइमन ग्रांट ने बताया कि शरद पवार तेजी से ठीक हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर सामान्य सीमा के भीतर हैं। उनकी समग्र नैदानिक स्थिति स्थिर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं।'' डॉक्टर ने बताया कि भर्ती के समय उन्हें जो हल्की परेशानी हो रही थी, वह लगातार चिकित्सा प्रबंधन से ठीक हो गई है''।

ग्रांट ने कहा, एहतियात के तौर पर, उन्हें अभी निगरानी में ही रखा गया है। उनका इलाज रूबी हॉल क्लिनिक के स्थापित चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया जा रहा है।''

उन्होंने कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के आधार पर आगे की उपचार प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। अस्पताल ने राकांपा (एसपी) कार्यकर्ताओं और शरद पवार के शुभचिंतकों से अपील की है कि वे अस्पताल में इकट्ठा न हों ताकि नियमित रोगी देखभाल में कोई बाधा न आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार मुंह के कैंसर के मरीज रहे हैं। उनके भतीजे एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गयी थी। अजित पवार की पत्नी एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ सोमवार शाम शरद पवार का हालचाल जानने अस्पताल आयी थीं।

लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रयासों की तरह ही अतीत में भी इस तरह की कुछ कोशिशें की गई हैं, लेकिन सफल नहीं हुईं। कई विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा है।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अतीत में, कुछ लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संबंधी नोटिस लाने के वास्ते कम से कम दो लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। नोटिस पर कितने भी सदस्य हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 94 सी में इस प्रकार के प्रावधान हैं।

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी ने पीटीआई-भाषा' को बताया, बहुमत की गणना के लिए सदन के सभी सदस्यों की गिनती की जाती है, न कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की, जो कि सामान्य प्रक्रिया है।

इसका अर्थ यह है कि रिक्तियों को छोड़कर सदन की प्रभावी सदस्यता का उपयोग बहुमत की गणना के लिए किया जाता है।'' उन्होंने कहा कि नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा जाता है, न कि लोकसभा उपाध्यक्ष या किसी अन्य को। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में दस्तावेज की जांच की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि इसमें बहुत विशिष्ट आरोप'' तो नहीं हैं।

आचारी ने विस्तार से बताया, प्रारंभिक स्तर पर ही स्वीकार्यता की प्रक्रिया होती है। उस चरण में यह देखा जाता है कि क्या इसमें विशिष्ट आरोप शामिल हैं। विशिष्ट आरोप आवश्यक हैं क्योंकि तभी अध्यक्ष जवाब दे सकेंगे।'' प्रस्ताव में मानहानिकारक भाषा या सामग्री नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष को सदन में अपना बचाव करने का अवसर प्रदान करता है। प्रस्तावित प्रस्ताव की भाषा की जांच आमतौर पर लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन चूंकि वर्तमान लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं हैं, इसलिए संभवतः इसकी जांच पीठासीन सभापति की समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाएगी।

यह समिति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन करने में उनकी सहायता करती है। आचारी ने कहा, अध्यक्ष द्वारा अपने ही निष्कासन से संबंधित प्रस्ताव की जांच करना हास्यास्पद प्रतीत होता है।'' उन्होंने कहा कि इस विषय पर नियम में कोई उल्लेख नहीं है। आचारी ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव सदन में पहुंचता है। लेकिन यह 14 दिनों के बाद ही सदन में जा सकता है। इसके बाद, अध्यक्ष इसे सदन में विचार किये जाने के लिए रखते हैं। वास्तव में सदन ही इसे स्वीकार करता है, या नियम के अनुसार, अनुमति प्रदान करता है।

आचारी ने कहा, ''अध्यक्ष तब प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं। यदि 50 सदस्य इसके समर्थन में खड़े होते हैं, और मानदंड पूरा होता है, तो अध्यक्ष सदन द्वारा अनुमति की घोषणा करते हैं। सदन द्वारा अनुमति मिलने के बाद, इसे चर्चा के लिए लिया जाता है और 10 दिनों के भीतर इसका निस्तारण करना होता है।'' प्रस्ताव पेश किए जाने के ऐसे कई उदाहरण हैं। हालांकि, अभी तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। आचारी ने कहा, इसका कारण है कि सरकारों के पास बहुमत होता है।

राहुल गांधी, कांग्रेस को राजनीति से बाहर करने का समय आ गया है : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

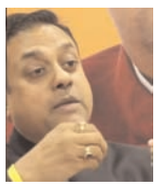

नई दिल्ली। भाजपा ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपे जाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। पार्टी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को राजनीति से बाहर कर दे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में बिरला के खिलाफ विपक्ष के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, जिन लोगों की चेतना नष्ट हो चुकी है, वे भारत के सभी संवैधानिक पदों को समाप्त करना चाहते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं एवं पदों पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने की इजाजत न देने तथा सदन की अवमानना के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा। कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश की ओर से लोकसभा महासचिव को सौंपे गए प्रस्ताव पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और कई अन्य विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

असम में अंतिम मतदाता सूची जारी, मसौदा सूची में शामिल 2.43 लाख से अधिक नाम हटाए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम में अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई, जिसमें मसौदा सूची में शामिल 2.43 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची में लगभग 12.5 करोड़ पुरुष, 12.4 करोड़ महिला और 343 तृतीय लिंग मतदाताओं के नाम शामिल हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें कुल 2.49 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि यह संख्या मसौदा मतदाता सूची में शामिल नामों से 0.97 फीसदी कम है। इसमें कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची में मसौदा सूची में शामिल 2.43 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। बयान के मुताबिक, पिछले साल 27 दिसंबर को प्रकाशित मसौदा सूची में 2.52 करोड़ मतदाताओं के नाम थे। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

केंद्र पता लगाए, बच्चों के लापता होने के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह का हाथ तो नहीं : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह या राज्य-विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई निश्चित पैटर्न है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। उसने केंद्र को सभी राज्यों से आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण करने का निर्देश दिया।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उनसे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, लेकिन लगभग एक दर्जन राज्यों ने अपना डेटा साझा नहीं किया है। भाटी ने दलील दी कि विश्लेषण तभी किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार को पूरा डेटा हासिल हो जाए। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के लापता होने की इन घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी गिरोह या राज्य-विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है? क्या इन घटनाओं के पीछे एक विशिष्ट पैटर्न है या ये महज आकस्मिक घटनाए हैं? शीर्ष अदालत ने भाटी को सुझाव दिया कि बचाए गए बच्चों से बात की जानी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। पीठ ने उन राज्यों की आलोचना की जिन्होंने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह कड़े आदेश पारित कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहल की है और सभी राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। पीठ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) गुड़िया 'स्वयं सेवी संस्थान' की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कई राज्यों में लापता बच्चों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को रेखांकित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नौ दिसंबर को केंद्र सरकार को लापता बच्चों के सिलसिले में छह साल का राष्ट्रव्यापी डेटा उपलब्ध कराने और ऐसे आंकड़ों के संकलन में राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक समर्पित अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की निगरानी के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि ऐसी जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से संचालित पोर्टल पर तुरंत अपलोड की जाए। न्यायालय ने 18 नवंबर 2025 को एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए चिंता जाहिर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। उसने बच्चों की गुमशुदगी को एक गंभीर मुद्दा बताया था।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मैक्रों 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

इसके अतिरिक्त, दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मोदी और मैक्रों मुंबई में संयुक्त रूप से 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' का उद्घाटन करेंगे।

अमेरिका के साथ 'डील' नहीं, 'ढील' हुई : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ 'डील' नहीं, 'ढील' हुई है तथा जब इसी तरह का व्यापार समझौता करना था तो फिर 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह कटाक्ष भी किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्वदेशी' और आत्मनिर्भरता' जैसे शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने देश बचे हैं जिनसे मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। सपा नेता ने दावा किया, ''अमेरिका के साथ डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया।'' उन्होंने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 18 प्रतिशत शुल्क और अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य शुल्क का हवाला देते हुए कटाक्ष किया, ''हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि शून्य बड़ा है या 18? क्या भाजपा का गणित यह है कि शून्य और 18 बराबर हैं?''

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो देश के किसान क्या उगाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। यादव का कहना था कि इस बजट में 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान और मजदूर बजट में अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देख रहे हैं।'' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ''प्रधान संसदीय क्षेत्र'' वाराणसी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

यादव ने दावा किया, वाराणसी में वहां लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। नेपाल नरेश की ओर भेंट किया गया घंटा भी लापता है। सपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी कोशिश के तहत उसने अयोध्या के 72 वर्षीय एक बुजुर्ग को बलात्कार के फर्जी मामले में कई महीनों तक जेल में रखा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जिस गांव को गोद लिया था उसे बेसहारा छोड़ दिया गया।

'प्री-ऑर्डर' के लिए उपलब्ध पुस्तक और प्रकाशित पुस्तक का मतलब एक नहीं : पेंगुइन प्रकाशन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित' पुस्तक को लेकर चल रहे विवाद के बीच, प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) ने मंगलवार को कहा कि किसी पुस्तक के बारे में घोषणा या पूर्व-ऑर्डर' के लिए इसकी उपलब्धता को प्रकाशन नहीं समझा जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देने के बाद पीआरएचआई' ने स्पष्टीकरण जारी किया। नरवणे ने उस पोस्ट में लोगों को सूचित किया था कि विचाराधीन संस्मरण, ''फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी'', अब उपलब्ध है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में पुस्तक प्रकाशन कैसे करता है, इस बारे में ''एक त्वरित मार्गदर्शिका'' शीर्षक के तहत अपने बयान में, प्रकाशक ने कहा, ''घोषित पुस्तक, प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध पुस्तक और प्रकाशित पुस्तक का मतलब एक नहीं हैं।'' इसमें आगे निर्धारित बिंदुओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी पुस्तक की घोषणा की जाती है, तो इसका मतलब केवल यह होता है कि प्रकाशक ने भविष्य में इसे प्रकाशित करने की योजना

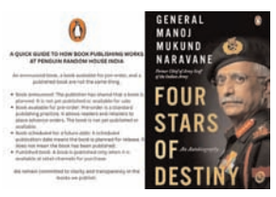

साझा की है और यह पुस्तक अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बयान में कहा गया है कि इसी तरह, किसी पुस्तक को 'प्री-ऑर्डर' के लिए सूचीबद्ध करना एक मानक प्रकाशन प्रथा है, जो पाठकों और खुदरा विक्रेताओं को प्रकाशन से पहले अग्रिम ऑर्डर देने की अनुमति देती है। बयान में यह भी जोड़ा गया है कि इस प्रकार सूचीबद्ध करने का मतलब यह नहीं है कि पुस्तक प्रकाशित या 'उपलब्ध' हो गई है।

प्रकाशक ने कहा कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि केवल एक नियोजित प्रकाशन समयसीमा दर्शाती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। बयान में कहा है, पुस्तक तभी प्रकाशित मानी जाती है जब वह खुदरा विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए उपलब्ध हो।

नरवणे के संस्मरण की कोई भी प्रति प्रकाशित नहीं की गई : प्रकाशक

नई दिल्ली/भाषा। 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' (पीआरएचआई) ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्रकाशन ने बयान में कहा कि पुस्तक की 'मुद्रित या डिजिटल' किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। प्रकाशक ने कहा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है।'' बयान में है कि ''कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा।

नरवणे ने अपनी किताब का लिंक 2023 में साझा किया था, वह झूठ नहीं बोलेंगे : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की पुस्तक को लेकर एक प्रकाशक ने इसके प्रकाशित नहीं होने की बात की है, लेकिन खुद नरवणे ने 2023 में एक ट्वीट् करके अपनी पुस्तक को खरीदने की अपील करते हुए एक लिंक साझा किया था। राहुल ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नरवणे की बात पर भरोसा है तथा उनकी किताब में कुछ ऐसी बाते हैं जो सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को असहज कर सकती हैं।

दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। उसने सोमवार को एक बयान में कहा था, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच और ऑनलाइन समाचार मंचों पर प्रसारित हो रही उन सूचनाओं का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नामक पुस्तक की एक प्रति सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रसारित की जा रही है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में कहा, ''नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है, मेरी किताब का लिंक फ़ॉलो कीजिए। अब या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन' (प्रकाशक) झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व थलसेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पेंगुइन कहता है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट किया है कि कृपया मेरी किताब ख़रीदिए। मैं पेंगुइन के बजाय नरवणे जी पर भरोसा करता हूं।'' उन्होंने सवाल किया कि क्या पेंगुइन पर नरवणे से ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? राहुल गांधी ने कहा, ''मेरा मानना है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं। स्पष्ट है कि आपको यह तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व थलसेना प्रमुख।''

सुविचार

खुश रहा करो क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सुविधाओं के आदी न हो जाएं नौनिहाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में विद्यार्थियों को दी गई यह सलाह अत्यंत उपयोगी है कि 'खुद को प्रौद्योगिकी का गुलाम न बनाएं, इसका उपयोग क्षमता बढ़ाने में करें।' वैज्ञानिक उन्नति के दौर में कई विद्यार्थी प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। यह प्रवृत्ति उनके विकास में बाधक बन सकती है। अब हर मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है। कई विद्यार्थी गणित के सवाल हल करते समय खुद गणना करने के बजाय कैलकुलेटर की मदद ले रहे हैं। जो विद्यार्थी लंबी अवधि तक ऐसा करते हैं, वे गणना एवं विश्लेषण में पिछड़ सकते हैं। नब्बे के दशक में जब बाजारों में विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटर उपलब्ध होने लगे थे, तब कुछ विद्यार्थी उत्सुकतावश पढ़ाई में उनका इस्तेमाल करते थे। धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। अगर कोई विद्यार्थी हफ्तेभर पढ़ाई के दौरान कैलकुलेटर पर ही निर्भर रहे और उसके बाद खुद गणना की कोशिश करे तो उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब फोन में कैलकुलेटर के साथ एआई प्लेटफॉर्म भी हैं, जो हर सवाल का जवाब सेकंडों में देते हैं। इनसे जानकारी जरूर मिल जाती है, लेकिन ये विद्यार्थियों की रचनात्मकता और कौशल में कितनी वृद्धि करते हैं? छठी कक्षा के एक विद्यार्थी को गृहकार्य में किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने के बजाय मोबाइल फोन में एक एआई प्लेटफॉर्म खोला और निबंध का विषय उस पर टाइप कर दिया। पलक झपकते ही उसके सामने पूरा निबंध तैयार था। उसने वही लिख दिया।

सवाल है- जब परीक्षा में किसी अन्य विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा तो वह विद्यार्थी कैसे लिखेगा? वहां तो मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी! क्या इस पर निर्भरता से प्रदर्शन कमजोर नहीं होगा? जब यह विद्यार्थी दसवीं कक्षा में पहुंचेगा, तब उसका प्रदर्शन कैसा होगा? सर्च इंजन, एआई और अन्य ऐप्स की उपयोगिता है, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है। इन्हें अपनी बुद्धि और विवेक का स्थान नहीं देना चाहिए। इनके जरिए अपने कौशल में सुधार लाएं। इन्हें सवाल पूछने के लिए कहें और खुद जवाब दें। इस तरह विद्यार्थी अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं। परीक्षा से कुछ दिन पहले एआई प्लेटफॉर्म पर किया गया अभ्यास काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ बच्चे खाना खाते समय भी मोबाइल फोन के साथ व्यस्त रहते हैं। वहीं, कुछ बच्चे उस समय टीवी देखना पसंद करते हैं। वे दस-पंद्रह मिनट में खाना खा लेते हैं। उसके बाद उनकी नजरें स्क्रीन पर जमी रहती हैं। उन्हें घंटाभर बाद याद आता है कि काफी समय बीत गया। कुछ बच्चे अन्य सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। अगर उन्हें 200 मीटर दूर भी जाना हो तो पैदल चलने से परहेज करते हैं। वे गर्मियों में एसी के बिना नहीं रह सकते। उन्हें मटके का पानी अच्छा नहीं लगता। वे रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। यह आदत सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। जब किसी कारणवश उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो बहुत परेशानी महसूस करते हैं। दिल्ली के एक महंगे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जब राजस्थान के अलवर में अपने ननिहाल आया तो अपनी नानी से शिकायत करने लगा, 'आपने मुझे यहां बुलाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी!' वजह- ननिहाल में एसी, रेफ्रिजरेटर, कार जैसी सुविधाएं नहीं थीं। बच्चों को सुविधाएं जरूर दें। उन्हें प्रकृति के साथ जीना भी सिखाएं। कहीं ऐसा न हो कि बच्चे सुविधाओं के इतने आदी हो जाएं कि उनमें मेहनत करने और परिस्थितियों से जूझने का साहस ही न रहे।

ट्वीटर टॉक

जयपुर के आराध्य प्रभु श्री गोविन्द देव जी के चरणों में आज शीश नवाकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस पावन अवसर पर जय निवास उद्यान से विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

-भजनलाल शर्मा

आज सचिवालय स्थित कार्यालय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारी देवतुल्य जनता एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं से आत्मीय भेंट कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

-दिया कुमारी

मेरे पिता स्व. राजेश पायलट जी ने जीवन भर किसानों, युवाओं एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम किया। एयरफोर्स में रहते हुए उन्होंने अपने साहस और अनुभव से देश की सीमाओं की रक्षा की।

-सचिन पायलट

प्रेरक प्रसंग

बलिदान से कर्ज अदायगी

युद्ध खत्म होने के बाद सिपाही विलियम स्कॉट रात के पहरे पर था। दिन की ड्यूटी करके अपने साथी सैनिक के स्थान पर वह दोबारा ड्यूटी पर तैनात हुआ था। थकावट के कारण खड़े-खड़े उसे नींद आ गई। तभी एक उच्च अधिकारी ने विलियम को रंगे हाथों पकड़ लिया। न्यायालय ने उसको प्राणदंड की सजा सुना दी। संयोग से राष्ट्रपति लिंकन को विलियम स्कॉट के प्राणदंड की खबर मिली तो वे सिपाही के पास जा पहुंचे। विलियम उनके पांवों से लिपट गया। राष्ट्रपति ने विलियम को उठाते हुए कहा, 'मैं तुम्हें इस सजा से छुड़वा दूंगा, मगर तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना पड़ेगा।' 'मैं अपनी जान की खातिर घर-बार बेचकर पांच-छह सौ डालर भेंट कर सकता हूं।' स्कॉट बोला। 'मगर मांग इससे बहुत ज्यादा है। इसे तुम्हारे हितैषी और बाप-दादा नहीं चुका सकते। इसे सिर्फ तुम्हें चुकता करना होगा।' लिंकन ने दृढ़ता से कहा। 'मगर कैसे?' स्कॉट ने सवाल किया। राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि, 'यदि तुम ताउम्र ईमानदारी से काम करोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरा कर्ज चुका दिया।' स्कॉट ने उनको यकीन दिलाया। कुछ दिनों बाद पुनः युद्ध छिड़ा तो स्कॉट जोश-खरोश से लड़ाई में कूद पड़ा और वीरता से लड़ते-लड़ते शहीद हो गया।

सामयिक

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वासः लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

ललित गर्ग

मोबाइल 9811051133

अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी लोकतंत्र के लिये एक चिन्ताजनक घटना है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, असहमति के सम्मान और संस्थागत विश्वास पर टिकी हुई एक जीवंत परंपरा है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसद इस लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहाँ न केवल नीतियाँ बनती हैं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आती हैं, तो यह घटना किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित न रहकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उन्हें, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को, सदन में बोलने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा, और इसी आधार पर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, एक गहरी चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए भी अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं।

विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहाँ तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।

यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतः अनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है तथा संसदीय परंपराओं और नियमों के पालन पर बल दिया है। उनकी छवि एक ऐसे अध्यक्ष की रही है जो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए होशियारी, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संसदीय मर्यादाओं का आग्रह और संवाद के लिए दरवाज़े खुले रखने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके जैसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

नजरिया

मानसिक तनाव से जूझते समाज की बिखरती संवेदनाएं

देवेंद्र सिंह

मानसिक तनाव आज केवल किसी एक व्यक्ति की निजी परेशानी नहीं रहा, बल्कि यह एक गंभीर और तेजी से बढ़ती वैश्विक चुनौती बन चुका है। बदलती जीवन शैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल निर्भरता और सामाजिक अपेक्षाओं ने इंसान के भीतर ऐसा दबाव पैदा कर दिया है, जिसे वह रोजमर्रा की मुस्कान के पीछे छिपाकर जी रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर मन थक चुका होता है। यही थकान धीरे-धीरे चिंता, बेचैनी और निराशा में बदल जाती है, जो जीवन की दिशा और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है। हाल ही में संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण व युनियन बजट में मानसिक तनाव, विशेष रूप से डिजिटल एडिक्शन से उपजी समस्याओं को एक बड़े स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिम के रूप में चिह्नित किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य अब केवल लाइफस्टाइल इश्यू नहीं रहा, बल्कि देश की उत्पादकता, सामाजिक संतुलन और युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। भारत में 60 प्रतिशत से अधिक मानसिक विकार 35 वर्ष से कम आयु के लोगों में पाए जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी इस संकट की सबसे बड़ी मार झेल रही है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत में लगभग 80 से 85 प्रतिशत लोग, जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें समय पर या उचित उपचार नहीं मिल पाता। इसके पीछे जागरूकता की कमी, सामाजिक झिझक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता बड़ी वजह हैं। 2024-25 के ताजा आंकड़े इस स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। शहरी भारत में लगभग हर दूसरा व्यक्ति तनाव से प्रभावित है। इप्सोस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सर्वे के अनुसार, 53 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष में उनका तनाव इतना बढ़ गया कि उनके दैनिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ा। एक अध्ययन में यह भी सामने आया कि लगभग 40 प्रतिशत किशोर चिंता और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। डिजिटल युग ने जहां जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मानसिक शांति को चुनौती भी दी है। मोबाइल और स्क्रीन की लगातार उपस्थिति नींद को प्रभावित कर रही है, एकाग्रता कम कर रही है और मन में अस्थिरता पैदा कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि 25 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने इतना गहरा मानसिक दबाव महसूस किया कि उन्हें हफ्तों तक सामान्य दिनचर्या निभाने में कठिनाई हुई। कार्यस्थलों पर लंबे समय तक काम, प्रदर्शन का दबाव और बर्नआउट अब आम समस्या बन चुके हैं।

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हुए इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भी विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार, भारत में मानसिक विकारों से ग्रस्त 70 से 92 प्रतिशत लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता। इसका एक बड़ा कारण देश में मनोचिकित्सकों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए, जबकि भारत में यह संख्या केवल 0.75 है। फिर भी एक सकारात्मक संकेत यह है कि अब लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं। लगभग 58 प्रतिशत भारतीय अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए तैयार हैं। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ जीवन जी रहे हैं। इसका अर्थ है कि विश्व का लगभग हर आठवां व्यक्ति मानसिक बीमारी से प्रभावित है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विकारों का प्रसार अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है। वहीं एशिया के कुछ देशों जैसे वियतनाम, थाईलैंड और लाओस सहित निम्न-आय वाले क्षेत्रों में इनकी दर अपेक्षाकृत कम पाई गई है। चीन में भी अवसाद के मामलों की दर कई विकसित देशों की तुलना में कम बताई गई है।

टेली-मानस परियोजना की प्रोजेक्ट मैनेजर अर्चना कार्तिक के अनुसार, भारत में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) ने वर्ष 2022 में टेली-मानस हेल्पलाइन शुरू की। वर्ष 2026 की हालिया रिपोर्ट बताती है कि इस सेवा पर प्रतिदिन औसतन करीब 3,500 कॉल प्राप्त हो रही हैं, जबकि अब तक 32 लाख से अधिक लोग इससे सहायता ले चुके हैं। यह सेवा 14416 नंबर पर 20 भाषाओं में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध है। हेल्पलाइन पर संपर्क करने वाले अधिकांश लोग पारिवारिक समस्याओं, पढ़ाई के दबाव, नशे की लत, वित्तीय तनाव, स्मृति संबंधी कठिनाइयों और अन्य मानसिक उलझनों से जूझ रहे होते हैं। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में बढ़ती जागरूकता और सहायता की जरूरत को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

आधुनिक जीवन शैली ने पारिवारिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित किया है। संयुक्त परिवारों का टूटना, एकल परिवारों का बढ़ना और आपसी संवाद में कमी मानसिक तनाव को और गहरा कर रही है। रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में लोग अपने घरों से दूर हो रहे हैं, जिससे पारंपरिक भावनात्मक सहारा कमजोर पड़ रहा है। आर्थिक असुरक्षा, सीमित आय, परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव और रिश्तों में बढ़ती दूरी मन को अस्थिर कर देती है। पति-पत्नी के बीच मतभेद, पारंपरिक और आधुनिक सोच का टकराव तथा रिश्तों में अनावश्यक हस्तक्षेप पारिवारिक तनाव को जन्म देते हैं। आज मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती काम नहीं, बल्कि काम से जुड़ा दबाव और समाज में बनी इमेज है। परिवार की उम्मीदें, रिश्तेदारों की तुलना और लोग क्या कहेंगे का डर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। हम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटते रहते हैं। यही मानसिक दबाव धीरे-धीरे शरीर और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है।

इसके लक्षण समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। लगातार चिंता, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, नींद की समस्या, शारीरिक थकान, सामाजिक अलगाव और भावनात्मक असंतुलन। ऐसे संकेत लंबे समय तक बने रहें तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर परामर्श और उचित उपचार मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। इसका सबसे गहरा असर बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। पारिवारिक कलह, संवाद की कमी और माता-पिता की बढ़ती महत्वाकांक्षा उनके मन पर गहरा प्रभाव डालती है। बेहतर अंक और ऊंचे करियर की उम्मीदें कई बार बच्चों को अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर कर देती हैं। जब अपेक्षाएं संवाद से बड़ी हो जाती हैं, तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है।

समाधान की शुरुआत परिवार से ही होती है। खुला संवाद, एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और अपनापन ही मानसिक सुकून की पहली सीढ़ी है। बच्चों को तुलना नहीं, सहयोग की जरूरत होती है। युवाओं को आलोचना नहीं, विश्वास चाहिए और बुजुर्गों को उपेक्षा नहीं, सम्मान और साथ चाहिए। यदि तनाव अधिक बढ़ जाए तो विशेषज्ञों से सलाह लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ क्लीनिक की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और उच्च तनाव वाले पेशों के लिए नियमित काउंसलिंग आज समय की मांग है। परिवार का टूटना केवल सामाजिक ढांचे का बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक पीड़ा है। संवेदनशीलता, समझ और आपसी सहयोग से ही इस पीड़ा को कम किया जा सकता है। जब समाज सफलता से पहले इंसानियत को महत्व देना शुरू करेगा, जब उपलब्धियों से पहले खुशहाली को प्राथमिकता दी जाएगी और जब संवाद को चुप्पी पर तरजीह मिलेगी, तभी मानसिक स्वास्थ्य का वास्तविक संरक्षण संभव होगा। मानसिक सुकून कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। जब तक इंसान अपने मन को समझना नहीं सीखेगा, तब तक बाहरी सफलताएं भी उसे सच्ची शांति नहीं दे पाएंगी।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

बांग्लादेश में दुकान के भीतर 62-वर्षीय हिंदू व्यापारी की हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में अज्ञात लोगों ने 62-वर्षीय एक हिंदू व्यापारी की उसकी दुकान के अंदर धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गयी है। त्रिशाल पुलिस थाने के प्रमुख मोहम्मद फिरोज हुसैन ने समाचार पोर्टल 'बीडीन्यूज24डॉटकॉम' को बताया कि यह घटना सोमवार रात उपजिला के बोगर बाजार चौराहे पर हुई।

उन्होंने बताया कि पीड़ित की पहचान साउथकंडा गांव के निवासी सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, जो भाई भाई एंटरप्राइज'' के मालिक थे। हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने सरकार पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद उसे दुकान के अंदर छोड़ दिया तथा शटर बंद कर दिए। सरकार का परिवार उसे ढूंढ रहा था और जब उन्होंने दुकान के शटर खोले, तो वह खून से लथपथ पाया गया।

सरकार को तुरंत मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित के बेटे सुजान सरकार ने बताया, हमारा चावल का पुराना कारोबार है। किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अपराधियों ने मेरे पिता की बेरहमी से हत्या करने के बाद दुकान से कई लाख टका लूट लिये।'' उन्होंने मांग की कि उनके पिता के हत्यारों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार की हत्या अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा की नवीनतम घटना है।

दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदू आबादी कई घटनाओं से प्रभावित हुई है। पिछले महीने बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद' ने आरोप लगाया था कि जैसे-जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। परिषद ने कहा कि उसने अकेले दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज कीं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होंगे। अगस्त 2024 में व्यापक जन आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के उपरांत बांग्लादेश में पहला चुनाव होगा।

फिल्म 'घूसखोर पंडत' का नाम बदला जाएगा

नई दिल्ली / भाषा। नेटफ्लिक्स इंडिया' ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म घूसखोर पंडत' का नाम बदल दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने यह बयान न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के सामने दिया, जो फिल्म के 'आपत्तिजनक' और 'बदनाम करने वाले' नाम की वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। न्यायमूर्ति कौरव ने कहा, निर्माता ने फिल्म का नाम 'घूसखोर पंडत' से बदलकर दूसरा नाम रखने का सोच-समझकर फैसला किया है, जो फिल्म की कहानी और मकसद को ज्यादा सही तरह से दिखाता है।'' नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि फिल्म का संपादन किया जा रहा है और यह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है।

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस

मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था आरोपी आसाराम

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म निर्माता- निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच नए-नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस के हाथ नई जानकारी लगी है। पता चला है कि हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार आरोपी आसाराम फासले पिछले चार सालों से बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। आसाराम मैकेनिक की आड़ में यह सब कर रहा था। फासले पुणे के मालवली इलाके का रहने वाला है और पिछले दस साल से वारजे क्षेत्र के एक गैरेज में मैकेनिक के तौर पर काम करता आ रहा था। जांच में सामने आया कि वह शुभम लोनकर से बहुत प्रभावित था। लोनकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सदस्य है।

फासले ने चार साल पहले लोनकर के प्रभाव और इलाके में उसके दबदबे को देखकर बिश्नोई गैंग जॉइन कर लिया था। तब से वह लोनकर का खास गुर्गा बनकर गैंग के लिए काम करता रहा। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में पहले गिरफ्तार चार आरोपियों में से फासले स्वप्निल सकट को अच्छी तरह जानता था। दोनों की मुलाकात लोनकर के जरिए हुई थी। फासले को लगता था कि गैंग में शामिल होने से उसके इलाके में भी उसका प्रभाव बढ़ेगा। उसके करीबी सर्कल के कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी, लेकिन वे गैंग से जुड़े हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही है।

पुलिस के अनुसार, लोनकर के निर्देश पर फासले ने स्वप्निल सकट को हथियार सौंपे थे। बाद में सकट ने उन हथियारों को अज्ञात शूटर को फायरिंग के लिए दिए। फासले को हथियार सप्लाई के बदले कितने पैसे मिले और हथियार उसने कहां से लिए, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब तक गिरफ्तार पांचों आरोपी लोनकर से प्रभावित होकर और इलाके में दबदबा बनाने के मकसद से बिश्नोई गैंग में शामिल हुए थे। रोहित शेट्टी के आवास पर हुए हमले के मामले को लेकर पुलिस अलर्ट है। हालांकि, असली शूटर तक नहीं पहुंच पाई है।

रिलायंस कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स ने हेल्थ फूड ब्रांड 'मन्ना' का अधिग्रहण किया

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने तमिलनाडु की प्रमुख हेल्थ फूड कंपनी सदर्न हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। कंपनी अपने प्रमुख ब्रांड 'मन्ना' के लिए जानी जाती है। यह पिछले दो दशकों से उत्पादों का निर्माण कर रही है।

अब मन्ना आरसीपीएल के फूड्स और स्टेपल्स पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गई है। इसमें पहले से उधैयम, इंडिपेंडेंस और एसआईएल जैसे ब्रांड शामिल हैं। इससे मिलेट आधारित और हेल्थ फूड सेगमेंट में रिलायंस की मौजूदगी और मजबूत होगी।

आरसीपीएल के निदेशक टी. कृष्णकुमार ने कहा कि मन्ना तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों में एक भरोसेमंद हेल्थ फूड ब्रांड है। रिलायंस के मजबूत वितरण और सप्लाई चेन नेटवर्क के जरिए मन्ना के उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा।

जीनत अमान ने पुरानी मैगजीन की हेडलाइन पर ली चुटकी, कहा- 'हेटर्स तो हेट करेंगे ही'

मुंबई/एजेन्सी

बीते जमाने की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान भले ही बड़े पर्दे पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस से पुराने समय की बातें, फिल्मों के अनुभव और जीवन के सबक शेयर करती रहती हैं। सोमवार को अभिनेत्री ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक खास तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीर पुरानी मैगजीन का कवर है, जिसके फ्रंट पर जीनत की तस्वीर लगी है, लेकिन मैगजीन की हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि जीनत को हंसी भी आई और थोड़ा मजाक भी। जीनत ने लिखा, मैं इस मैगजीन की हेडलाइन को 'ऐसी चीजें जो समय के साथ बेहतर नहीं हुई' वाली कैटेगरी में डाल रही हूं। अच्छी बात ये है कि कम से कम

उन्होंने मेरी एक प्यारी तस्वीर तो चुनी है। जीनत ने आगे लिखा, शायद ये मैगजीन अब बंद हो चुकी है, लेकिन सोचिए कि उस समय की वो 'फेल' समझी जाने वाली महिला यानी कि मैं आज भी मौजूद हूं और इतने साल बाद भी फैंस के बीच लोकप्रिय हूं।

अभिनेत्री ने लिखा, धैर्य एक बड़ा गुण है। जैसा कि हाल ही में सेट पर एक युवा ने कहा था - 'हेटर्स तो हेट करेंगे'। मतलब, लोग निंदा करते रहेंगे, लेकिन सब्र रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जीनत का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अभिनेत्री की सीख को आगे आजमाने की बात भी कर रहे हैं। अभिनेत्री जीनत अमान ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार फिल्मों में काम किया है। सिनेमा में आने से पहले जीनत पत्रकार थीं। उन्होंने फिल्म 'हलचल' से अभिनय में कदम रखा, लेकिन खास पॉपुलैरिटी अभिनेत्री को फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' से मिली थी। इस फिल्म में अभिनेत्री ने देवानंद की बहन का रोल अदा किया था। फिल्म में सहायक भूमिका के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था।

राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा में दशकों से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव तिहाड़ जेल हैं क्योंकि अभिनेता 5 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में असमर्थ रहे। 6 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेता आत्मसमर्पण कर चुके हैं लेकिन अब अभिनेता सोनू सूद ने आगे आकर राजपाल यादव की मदद करने की ठानी है और इंडस्ट्री के बाकी लोगों से भी एकजुटता की अपील की है। समाज सेवा में बड़ा योगदान देने वाले सोनू सूद ने अब इंडस्ट्री के लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। अभिनेता इस बात से बहुत दुखी हैं कि दशकों से सबको गुदगुदाने वाला अभिनेता पैसों की तंगी से जूझ रहा है और जेल की सलाखों के पीछे है। अभिनेता को सपोर्ट करते हुए सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजपाल यादव एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जिन्होंने वर्षों तक हमारे उद्योग को अविस्मरणीय योगदान दिया है। कभी-कभी जीवन अन्यायपूर्ण हो जाता है, प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि समय के क्रूर होने की वजह से।

उन्होंने आगे लिखा, वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, और मेरा मानना ङ्कहै कि यह हम सभी के लिए निर्माताओं, निर्देशकों, सहकर्मियों के लिए एकजुट होने का क्षण है। भविष्य के कार्यों के बदले समायोजित की जाने वाली एक छोटी सी साइनिंग राशि दान नहीं, बल्कि सम्मान है। जब हमारे अपने किसी व्यक्ति को कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, तो इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इसी तरह हम यह दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री से कहीं अधिक हैं।यूजर्स भी अभिनेता सोनू के पोस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। राजपाल यादव 'सी कंपनी', 'भूल-भूलैया', 'अपना-सपना मनी-मनी', 'चुप-चुप के' जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेता ने सिर्फ कॉमेडी से नहीं, बल्कि गंभीर किरदारों से भी फैंस का दिल जीता है। राजपाल यादव फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, और जेल में सरेंडर करने से पहले उनके द्वारा कही गई भावुक बातें लगातार वायरल हो रही हैं। अभिनेता ने दुख जताते हुए कहा था कि क्या करें, पैसों की तंगी है, पैसा नहीं है, और कोई रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है। यहां कोई दोस्त है नहीं जो मदद कर सके।

विरोध

तेलंगाना इगझ कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हैदराबाद में तेलंगाना डीजीपी ऑफिस में चुनाव से पहले नारायणपेट में भाजपा म्युनिसिपल उम्मीदवार की कथित आत्महत्या को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

अनुपम खेर ने अपने नाम से बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर आगाह किया

नई दिल्ली/भाषा। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने उनके नाम से बनाए गए कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स को सतर्क किया है और उनसे ऐसे प्रोफाइल से आने वाले किसी भी अनुरोध को अनदेखा करने की अपील की है। खेर ने मंगलवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीरों एवं वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं को संदेश एवं अनुरोध भेज रहे हैं।

वीडियो में खेर यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजकर बताया कि किसी ने मेरे नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोल रखे हैं। उन्होंने मेरी प्रोफाइल तस्वीरें एवं वीडियो लगाए हैं और लोगों को अनुरोध भेज रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। कृपया उन्हें नजरअंदाज करें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैंने दूसरा अकाउंट क्यों खोला है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया।'' खेर ने स्पष्ट किया कि इंस्टाग्राम पर उनका केवल एक ही आधिकारिक अकाउंट है। अनुपम खेर की हालिया फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' है, जो 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए उन्होंने 2002 की ओम जय जगदीश' के बाद निर्देशन में वापसी की।

प्रदर्शन

पटना में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकर्ताओं ने पटना के आईटीओ गोलंबर पर बिहार विधान परिषद में की गई उनकी कथित टिप्पणियों के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया।

टीवी अभिनेत्री नेहा मलिक को ठगने वाले फर्जी पैकर्स-मूवर्स गैंग बेनकाब

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई के मालाड इलाके में टीवी अभिनेत्री नेहा मलिक को निशाना बनाकर की गई बड़ी ठगी का पर्दाफाश करते हुए कुरार पुलिस ने फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह खुद को नामी ट्रांसपोर्ट कंपनी बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और फिर कीमती घरेलू सामान लेकर फरार हो जाता था। अभिनेत्री नेहा मलिक उर्फ खुशी चौधरी ने 27 दिसंबर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये 'इनफील्ड लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स' नामक कंपनी से संपर्क किया था। अभिनेत्री नेहा मलिक मुंबई के मालाड के माउली अपार्टमेंट में रहती थी। उन्हें कांदिवली के लोखंडवाला में नए फ्लैट में शिफ्ट होना था। अभिनेत्री को परिवार में शादी के लिए गहने, कपड़े और सामान लेकर यूपी जाना था। आरोपी वैभव सिंह ने खुद को कंपनी का मालिक बताकर कम कीमत में घर का सामान शिफ्ट करने का भरोसा दिया। आरोपी वैभव सिंह ने 4 जनवरी को यूपी में बैठकर अपने पहचान वाले मजदूरों को मूवर्स पैकर्स वाला बताकर मालाड ईस्ट स्थित माउली अपार्टमेंट में अभिनेत्री के घर भेजा। मजदूरों ने कपड़े, मेकअप किट, जूते, बैग, पेंटिंग्स, शीशे और कीमती एंटीक सामान सहित कुल सामान को 18 बैग में पैक किया। पूर्व में अभिनेत्री ने शिफ्टिंग के बदले 11,700 रुपए ऑनलाइन क्यूआर कोड से भेज दिए थे। कीमती सामान देखने के बाद शिफ्टिंग के लिए मजदूरों ने ज्यादा पैसे वसूलने का प्लान बनाया। अगले ही दिन आरोपियों ने वजन और साइज का बहाना बनाकर बिल 25,506 तक

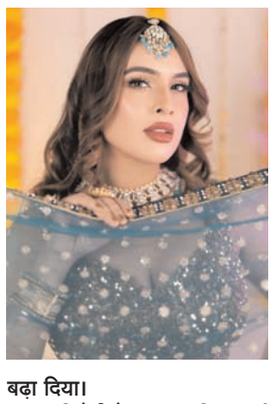

बढ़ा दिया।

अभिनेत्री ने जब आपत्ति जताई और सामान लौटाने को कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। कई बार संपर्क के बावजूद न तो सामान पहुंचाया गया और न ही वापस किया गया। मजदूरों ने अभिनेत्री के फ्लैट से उठाए सभी कीमती बॉक्स को मुंबई के अंधेरी साकीनाका समर्थ बिल्डिंग में छुपा दिया। अभिनेत्री के बार-बार पूछने पर भी आरोपी ने सामान नहीं दिया और फोन बंद कर दिए। इसके बाद अभिनेत्री ने कुरार पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की और साकीनाका समर्थ बिल्डिंग से अभिनेत्री का सामान बरामद किया। कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजीव तावड़े ने कहा कि पुलिस साकीनाका समर्थ बिल्डिंग पहुंची और तकनीकी निगरानी एवं जांच के आधार पर चोरी किया गया सामान एक गोदाम से बरामद किया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और सामान की जब्ती की गई।

पुलिस के मुताबिक, 28 जनवरी को छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी विजय रामावतार पाल (40) को गिरफ्तार किया, जो पेशे से मजदूर है और गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। विजय पाल सीधे तौर पर पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग में शामिल था। गैंग का मास्टरमाइंड वैभव सिंह समेत दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सारा सामान 2 फरवरी को अभिनेत्री को सौंप दिया गया। कुरार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैकर्स एंड मूवर्स की सेवाएं लेते समय कंपनी की पूरी जांच-पड़ताल और दस्तावेज सत्यापित करें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये ठगी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं। अभिनेत्री नेहा मलिक उर्फ खुशी चौधरी ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि कुरार पुलिस ने दिन-रात मेहनत कर गैंग को बेनकाब किया और मेरा पूरा सामान सुरक्षित वापस दिलाया। इनमें से कई चीजें बेहद कीमती थीं।

'बॉर्डर 2' के बाद अब 'लाहौर 1947' में धमाल मचाने को तैयार सनी देओल

मुंबई/एजेन्सी

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का जादू बॉक्स ऑफिस पर जारी है। इस बीच मेकर्स ने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। 'लाहौर 1947' 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के जरिए पहली बार सनी देओल, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर आमिर खान एक साथ काम करने जा रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा बनाई गई यह फिल्म साल 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय में से एक को खास अंदाज में पर्दे पर पेश करेगी। आमिर खान ने बताया कि यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की पसंदीदा स्क्रिप्ट थी। उन्होंने फिल्म को लेकर बताया, यह धरम जी (धर्मेंद्र) की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी। मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म उसी अंदाज में रिलीज होगी और इसे उनका प्यार मिलेगा।

अपकमिंग फिल्म की कहानी असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई' से प्रेरित है। यह नाटक विभाजन की बड़ी राजनीति के बजाय सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन से टूटे हुए रिश्तों पर फोकस करता है।

कहानी एक हिंदू परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे लाहौर से भारत आने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें एक मुस्लिम परिवार द्वारा छोड़ी गई हवेली मिलती है, लेकिन वहां एक बूढ़ी मुस्लिम महिला अभी भी रह रही होती है। इसके बाद विभाजन के उथल-पुथल भरे दिनों में पहचान, नुकसान और नैतिक जिम्मेदारी जैसे गहरे सवाल उठते हैं।

फिल्म तमाशे वाली देशभक्ति कहानियों से अलग हटकर विभाजन के स्थायी जख्मों, सहानुभूति और साझा दर्द पर रोशनी डालती है। यह एक भावुक और गंभीर पीरियड ड्रामा है। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जिसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। संगीत को एआर रहमान ने तैयार किया है और गीतों के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

'संस्कृति और एकता का उत्सव है हिंदू समाजोत्सव'

श्रीरामपुरम में हिंदू समाजोत्सव की भव्य शोभायात्रा निकाली गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के श्रीरामपुरम की हिंदू समाजोत्सव समिति द्वारा हिंदू समाजोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैंकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रख कर शोभायात्रा निकाली। इस शोभायात्रा में पालन मठ के मठाधीश सिद्धराजू स्वामी उपस्थित थे। शोभायात्रा विभिन्न स्थानों ने होते हुए डॉ बीआर अंबेडकर खेल मैदान पहुंची।

हिंदू समाजोत्सव समिति के अध्यक्ष महावीरचंद चोरड़िया जेके ने कहा कि हिंदू धर्म को आज विश्व स्तर पर विशेष मान्यता प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसकी आधारशिला सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और मानव कल्याण पर आधारित है। मुख्य वक्ता एसडीएम कॉलेज के सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक गोविंद ने कहा कि आज हिंदू समाज पूरी तरह जागरूक हो चुका है और उसमें अपनी संस्कृति, परंपरा तथा मूल्यों के प्रति सजगता बढ़ी है। कार्यक्रम में समणी निदेशिका डॉ सुयशनिधिजी एवं डॉ सुयोगनिधिजी, भाजपा बेंगलूरु सेंट्रल के अध्यक्ष सप्तगिरि गौड़ा आदि की विशेष उपस्थिति रही।इकार्यक्रम में विभिन्न सेवा प्रदान करने के लिए जैनम लक्ष्मीनारायणपुरम ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेशकुमार सियाल सहित अन्य पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया।

राजस्थानी तमिल सेवा अवॉर्ड्स के दूसरे संस्करण का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। संस्कृति सेवा और समर्पण के अद्भुत समागम के साथ राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु द्वारा राजस्थानी तमिल सेवा अवॉर्ड्स के दूसरे संस्करण का आयोजन रविवार को यहां एक होटल में आयोजित किया गया।

यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को समर्पित किया गया जिन्होंने तमिलनाडु और पांडिचेरी की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष इन पुरस्कारों हेतु 200 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिनमें से केवल 5 को अवॉर्ड्स के लिए चयन किया गया प्रत्येक अवॉर्ड्स प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र पदक और दो लाख रुपए की धन्साशि प्रदान की गई। ज्यूरी मंडल में एस गुरुमूर्ति, एन. रवि, पद्म विभूषण डॉ पद्मा सुब्रमण्यम प्रो ई बालगुरुस्वामी और समाजसेवी एवं उद्योगपति सुगलचंद जैन सम्मिलित थे।

मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीस आर महादेवन ने कहा कि जो समाज अपने नागरिकों की असाधारण सेवाओं का सम्मान करता हे वही पूरे विश्व में आदरणीय होता है। उन्होंने जलस्रोतों के संरक्षण और ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर बल दिया। अतिथि-विशेष एवं निर्णायक मंडल सदस्य एन. रवि ने राजस्थानी समुदाय की परोपकार और सेवा भावना को उल्लेखित करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संस्थाओं की स्थापना से यह समुदाय तमिलनाडु के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से जुड़ गया हैं। उन्होंने कहा कि 1967 में स्थापित राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु ने इस आयोजन के माध्यम से पुनः यह सिद्ध किया है कि राजस्थानी और तमिल समाज का सांस्कृतिक बंधन सेवा, समर्पण और सहयोग की नीव पर दृढ़ता से खड़ा है । इस अवसर पर राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीश्रीमाल ने कहा कि हमारे समुदाय की प्रगति तमिलनाडु की प्रगति से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि हम तमिल आदर्श याधुम करे यावरूम केलिर (सभी नगर हमारे है, सभी मनुष्य हमारे भाई हैं) कि विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थानी समुदाय शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, आभूषण, वित्त विनिर्माण और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में वृहद स्तर पर पहुंच चुका है इसके साथ ही हम समाजसेवा और परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय है, ताकि वंचितों, असहायों, गरीबों को सहारा दिया जा सके।

पांच सितारा होटल में आयोजित समारोह में पांच विशिष्ट व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राजस्थानी तमिल सेवा अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया जिनमें डॉ. सुधा शेषयन चिकित्सक, शिक्षाविद् एवं सांस्कृतिक विदुषी), बी. सरगुरुनाथन (कपालेश्वर मदिर के मुख्य ओदुवर एवं सैव संगीत परंपरा के संरक्षक) पाइर ट्रस्ट (ग्रामीण विकास में अग्रणी संस्था) के आर राजा (मानवाधिकार अधिवक्ता एवं सामाजिक सुधारक), पब्लिक हेल्य सेंटर, वेस्ट मंबालम (सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की सात दशक पुरानी धरोहर) शामिल रहे। इन सभी को समाज, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और ग्रामीण उत्थान में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रशस्ति-पत्र, पदक और दो लाख रुपए की धनराशि एसोसिएशन की ओर से बतौर पुरस्कार प्रदान किए गए।

टीना अंबानी को जल्द फिर से समन भेजेगा ईडी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 'रिलायंस ग्रुप' के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को जल्द नया समन जारी करेगा।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को सोमवार को यहां संघीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। उन्होंने बताया कि टीना को जल्द ही पूछताछ के लिए फिर बुलाया जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि उन्हें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेनदेन के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया गया था।

ईडी ने हाल में इस मामले में 'रिलायंस कम्युनिकेशन' (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ईडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी और उससे जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों की जांच के लिए हाल में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है।

आईओबी ने मनाया अपना स्थापना दिवस

चेन्नै। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आईओबी), अपना 90वाँ स्थापना दिवस मनाया इस मौके पर बैंक के संस्थापक एम. सीटी. एम. चिदंबरम चेट्टियार की विरासत को सम्मान दिया गया, जिन्होंने आज ही के दिन 1937 में बैंक की स्थापना की थी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंध निदेशक व सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक जयदीप दत्ता रॉय एवं धनराज टी, मुख्य सतर्कता अधिकारी राजीव कुमार और संस्थापक के परिजनों ने संस्थापक की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक और केंद्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर आइओबी ने पोषण पर फोकस करने वाले सीएसआर कार्यक्रम के ज़रिए आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान किया इस के साथ ही अक्षय पात्र फ़ाउंडेशन में योगदान दिया गया, जिससे चेन्नै के 43 स्कूलों में 7,584 छात्रों को नाश्ते में मदद मिलेगी । यह पहल बैंक के इस विश्वास को दर्शाती है कि अच्छी पढ़ाई और लंबे समय तक चलने वाली सामाजिक तरक्की की नींव का आधार अच्छा पोषण ही है। इसके अतिरिक्त

चेन्नई के पांच बड़े इलाकों में सैनिटेशन और हाइजीन किट बांटे गए, जिससे 4,000 लड़कियों और 10,000 घरों को फायदा हुआ। यह बेहतर हाइजीन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह पहल सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी समिति के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सबको साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत , बैंक ने 23 ज़रूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल बांटी, जिससे दिव्यांगों को चलने-फिरने की आज़ादी और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिले । आइओबी द्वारा किए गए इस पहल से उनकी उदारता की सोच और विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उसके समर्पण की भावना को दर्शाता है।

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी, आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई।बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अज्ञात व्यक्तियों ने व्हाट्सऐप के जरिए धमकी दी है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को एक 'वॉयस नोट' के जरिए धमकी मिलने और इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद, उनके आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंह को यह धमकी शहर में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के कुछ दिनों बाद मिली है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस को संदेह है कि जबरन वसूली के उद्देश्य से रणवीर सिंह को दी गई इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य मुंबई स्थित जिस हाउसिंग सोसाइटी में अभिनेता रहते हैं, वहां मुंबई पुलिस के कर्मियों के अलावा निजी गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

मंगलवार को सोसाइटी की प्रबंध समिति ने पुलिस से संपर्क किया और इन गार्डों की तैनाती पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक पत्र में कहा, चूंकि ये सशस्त्र गार्ड लॉबी, जिम और बच्चों के खेलने के क्षेत्र जैसे सामान्य स्थानों पर हथियारों के साथ बार-बार घूम रहे हैं, इससे सोसाइटी की प्रबंध समिति को अन्य निवासियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो रही है। हाल में, एक अज्ञात शूटर ने जुहू स्थित फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास पर पांच गोलियां चलाई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने कथित तौर पर उस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि फिलहाल फरार है।

खेलो में एआई नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बोनब्लॉक ने चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ साझेदारी की घोषणा की

चेन्नई। अग्रणी वैश्विक एआई और प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी बोनब्लॉक ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ अपनी आधिकारिक साझेदारी की घोषणा की है और इस सीजन में सीएसके के आधिकारिक एआई पार्टनर के रूप में फ्रेंचाइजी से जुड़ गई है। क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी में से एक सीएसके के साथ साझेदारी करके बोनब्लॉक ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मनोरंजन प्रदान करना और उन्हें बेहतरीन अनुभव देने के अपने प्रयास को जारी रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है इस अवसर पर बोनब्लॉक के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक दुरई अप्पादुरई ने कहा कि सीएसके के साथ हमारी साझेदारी प्रेरणा और ब्रांड पहचान का स्रोत है।

उन्होंने कहा कि हमारे युवा संस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर अवसर को जीतना चाहते हैं और प्रौद्योगिकी बाजार में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते है । हम सीएसके के आधिकारिक एआई पार्टनर बनकर बेहद उत्साहित हैं।

इस अवसर पर चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंध निदेशक काशी विश्वनाथन ने कहा कि हमे सीएसके के आधिकारिक एआई पार्टनर के रूप में बोनब्लॉक को घोषणा करते हुए खुशी हो रही है उन्होंने कहा कि बोनब्लॉक की एआई क्षमताओं के साथ हम नई संभावनाओं को खोजने के लिए तत्पर हैं। इस साझेदारी के तहत, बोनब्लॉक की ब्रांडिंग सीएसके के डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रमों और एआई और ब्लॉकचेन तकनीकों द्वारा संचालित विशेष पहलों में दिखाई देगी।

संत संस्कृति के रक्षक हैं : शंकराचार्य विजयेन्द्र सरस्वती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कांचीपुरम्। यहां काचीपुरम् शंकराचार्य मठ में मंगलवार को कांचीकामकोठी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य श्री विजयेन्द्र सरस्वती ने कहा कि संत जितना निर्भीक, निडर, निस्वार्थ, और निश्छल होगा। उतना ही आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए वरदान स्वरूप बनेगा। राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश के 70वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि संत संस्कृति का रक्षक संस्कारों का पुंज ज्ञान का भंडार चरित्र दर्पण है चलता फिरता तीर्थ है अभिनंदन स्वरूप माला समर्पित की। जगद्गुरु शंकराचार्य एवं जैन संतकमल मुनिजी कमलेश ने राज्य सरकार से कहा कि शंकराचार्य मंदिर से लेकर कामाक्षी मंदिर तक पवित्र स्थल घोषित किया जाए। संपूर्ण विश्व के आस्था का केंद्र है जहां से संतों का निकलना मुश्किल हो जाता है तो सामान्य जनता के क्या हाल होते होगा। यहां पूरे क्षेत्र में से शराब मांस और मछली की दुकान तत्काल हटानी होगी।

मुनि कमलेशजी बताया कि हरिद्वार और पालीतना साहित कई क्षेत्रों कि राज्य सरकारों ने पवित्र स्थल घोषित करके वहां पर शराब और मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु सरकार को भी जन भावना का सम्मान करते हुए तत्काल विश्व प्रसिद्ध आस्था के केंद्र धर्म स्थलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधना के लिए उचित पवित्र वस्तु होना भी अत्यंत जरूरी है। देश के सभी मंदिर में गाय के दूध से प्रसाद, पूजा, दीपक, आरती होनी चाहिए। हर मंदिर के साथ एक गौशाला होगी तभी पवित्रता संभव हो सकती है। शंकराचार्य ने भी इन विचारों का समर्थन किया। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि सात्विक आहार वृक्षारोपण जल शुद्ध गो संवर्धन गौ सेवा स्वच्छता अभियान को अपने पर जोर दिया नैतिकता और नशा मुक्ति जीवन समय की सबसे बड़ी मांग है। चर्चा में घनश्याम मुनिजी, सक्षम मुनिजी सत्य चंद्रशेखर इंद्र सरस्वती स्वामीजी, मैनेजर सुंदरेष अय्यर, अमृतलाल संचेती धर्मचंद काठेड़, राजेश सिसोदिया, महेंद्र संचेती, प्रशांत संचेती, प्रेमलता जैन ने भाग लिया। आगामी 13 से 15 फरवरी तक तिरुतनी गुरु जयमल जैन पार्श्व पद्मोदय गौशाला में जैन संत कमल मुनि कमलेश का 70 जन्मदिन मनाया जा रहा है।

प्रतिष्ठा

चेन्नई के माधावरम में कुमावत समाज में राधा कृष्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और राजस्थान और अन्य प्रांत से मेहमान पधारे। इस मंदिर की महोत्सव में जो राजस्थान के पुराने रीति रिवाज से 24 खेड़ा 12 पट्टी के पंच पहुंचें। भजन की प्रस्तुति सोनू महाराज और सोहन महाराज और अन्य संत प्रवचन दिए।

यदि भाषा विरोध बीमारी है, तो अधिकतर राज्य इससे ग्रस्त हैं : राज ठाकरे ने भागवत पर साधा निशाना

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के विचार में अपनी भाषा के पक्ष में प्रदर्शन करना एक बीमारी है, तो देश के अधिकतर राज्य इससे ग्रस्त हैं। ठाकरे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया कि सात और आठ फरवरी को आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर यहां आयोजित भागवत के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग उनके प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी सरकार के डर से आए थे। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि लोग आरएसएस के कार्यक्रमों में स्वेच्छा से और अनुशासन के साथ भाग लेते हैं।

मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे द्वारा भागवत की आलोचना किये जाने को भाव नहीं देने की कोशिश करते हुए कहा कि जिन लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, वे बुरा महसूस कर रहे थे। सत्तारूढ़ महायुति की अगुवा भाजपा ने कहा कि मराठी गौरव का विषय है, लेकिन किसी भी भाषा को संघर्ष का नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम बने रहना चाहिए।

भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा भगवान महावीर पुरस्कारों की घोषणा

चेन्नई। भगवान महावीर फाउंडेशन ने 29वें महावीर पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार विजेता अहिंसा एवं शाकाहार पर सरहद महाराष्ट्र को, शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के कोर्ड को, चिकित्सा के लिए कर्नाटक के श्री शंकरा कैंसर फाउंडेशन, समुदाय एवं सामाजिक सेवा के लिए मिजोरम की श्रीमती संगखुमी बुआलछुआक को और ओडिया के निर्माण संस्थान को दिया गया। ज्ञातव्य हो कि महावीर पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में दस लाख की नकद राशि, एक स्मृति-चिह्न और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

समाज के प्रति निःस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निरंतर 30 वर्षों से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में, फाउंडेशन ने इस वर्ष पाँच पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। वर्ष 2026 के पुरस्कार विजेताओं के चयन के साथ, महावीर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है, जो 26 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। पुरस्कारों का चयन बेंगलूरु में आयोजित बैठक में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया।'सरहद' पिछले चार दशकों से संवाद, शिक्षा, संस्कृति और जन-सम्पर्क के माध्यम से भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापना और राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य कर रहा है।कॉम्प्रिहेन्सिव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट (कोर्ड) शिक्षा आधारित समावेशन और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विशेष रूप से दिव्यांगजनों और महिलाओं सहित वंचित समुदायों को सशक्त बनाता है। इसके साथ ही बेंगलूरु और भुवनेश्वर में श्री शंकरा कैंसर फाउंडेशन अपने अस्पतालों के माध्यम से किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर चिकित्सा प्रदान करता है, जिसमें रोकथाम, निःशुल्क जांच, रियायती उपचार और समग्र रोगी देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसी क्रम में श्रीमती संगखुमी बुआलछुआक ने विधायी सुधारों, जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से मिज़ोरम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। 'निर्माण ओडिशा' के आदिवासी और वनवासी समुदायों के साथ मिलकर आजीविका, खाद्य सुरक्षा और महिलाओं के नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु कृषि-पर्यावरणीय खेती और सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है। इन पुरस्कारों का वितरण शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट अतिथि द्वारा किया जाएगा।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.